



04 - एआई की बुद्धिमत्ता और हमारी मूर्खताएं



05 - डेटा के जंगल में खोती मानवीय संवेदना

A Daily News Magazine

मोपाल

गुरुवार, 26 फरवरी, 2026



मोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 176, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - आयु सीमा पूर्ण करने के कारण अपात्र हुई महिलाएं



07 - कृषि रथ जिले के 4,656 गांवों में पहुंचकर 17,469...

कैलेंडर

प्रसंगवश

भारत के लिए अपना एआई स्टैक बनाना अब रणनीतिक जरूरत

मीनाक्षी लेखी

एक युवा महिला के रूप में, मैंने जॉर्ज ऑवेल की 1984 पढ़ी थी, जिसमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना की गई थी जहां तकनीक हर जगह मौजूद हो और हर चीज में दखल देने वाली हो। इसी लम्बाया तकनीक की निगरानी में था। यह भविष्य अब दूर नहीं है, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक ही छत के नीचे दिखाई गई सभी नई तकनीकों के साथ देखा।

यह हमारे लिए बहुत गर्व और राष्ट्रीय महत्व की बात थी कि हम दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच पाए और उसे बनाए रख पाए। इस कार्यक्रम में 5 लाख से ज्यादा लोग आए और कई और लोग ऑनलाइन जुड़े क्योंकि सत्र इंटरनेट पर उपलब्ध कराए गए थे। 88 देशों ने एआई पर नई दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर किए और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को स्वीकार किया कि तकनीक को लोकतांत्रिक बनाना जरूरी है ताकि बदलाव लाया जा सके।

गलोटिया गेट की शर्मनाक घटना और शोर-शराबे, और राहुल गांधी के बिनियान बायज के तमारे के धुंध से आगे बढ़ते हुए, यह दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन की सफलताओं और कमियों पर शांत होकर सोचने का समय है। आइए मुख्य बातों का विश्लेषण करें। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्लेनेट (पृथ्वी), पीपल (लोग) और प्रोग्रेस (प्रगति) के तीन सूत्रों का ढांचा पेश किया था। भारत के लिए यह विचार नया नहीं है, क्योंकि हमारी प्राचीन सोच मानती है कि पृथ्वी एक साझा विरासत है, कोई वस्तु नहीं। इसलिए एआई को शोषण का नहीं, बल्कि सबको

साथ लेकर चलने वाला एक साधन बनाना चाहिए। भारत का दृष्टिकोण तकनीकी बदलाव के केंद्र में प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि लोगों को रखता है और यही असली प्रगति का संतुलन है। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, 'यह माना जाता है कि यह शिखर सम्मेलन मानव-केंद्रित, संवेदनशील वैश्विक एआई इकोसिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।' इसलिए, असली प्रगति तब होगी जब तेजी से हो रहे नवाचार में मूल्य सबसे पहले आगे बढ़ें, जहां एआई समृद्धि बढ़ाए, लेकिन धर्म, समावेशिता और भरोसे से जुड़ा रहे।

वैश्विक कॉर्पोरेट नेता और भारत का टेक इकोसिस्टम देश को एआई के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर देख रहे हैं, जहां विशाल मानव संसाधन और डेटा का उपयोग करके भारत डीपटेक और एआई का लीडर बन सकता है। एआई जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वह एक केन्द्रापसारक बल (centrifugal force) की तरह है, जो अपने साथ बदलाव को तेज हवाएं ला रहा है। इस संदर्भ में, Sarvam एआई और BharatGen जैसे स्वदेशी मॉडलों का उभरना आम लोगों के लिए खुशी की बात ही हो सकती है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट के अनुसार, 'भारत के एआई मार्केट का आकार 2024 में 9.51 अरब डॉलर था और यह मार्केट 2025 में 13.05 अरब डॉलर से बढ़कर 2032 तक 130.63 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें अनुमानित अवधि के दौरान 39.00 प्रतिशत की CAGR होगी।' ये आंकड़े खुद ही सब कुछ बताते हैं। भारत उभरती एआई तकनीकों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और इसका बड़ा पैमाना इसे वैश्विक एआई कंपनियों के लिए एक आकर्षक बाजार बनाता है। इस

स्पीड को दिखाते हुए, शिखर सम्मेलन में 500 से ज्यादा एआई लीडर्स, 100 से ज्यादा संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, 150 शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, और लगभग 400 मुख्य तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था का 70 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल होगा। रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2028 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सकता है और केवल डिजिटल भूगतान 2026 में 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं। एआई की (बदलाव लाने वाली) क्षमता को ध्यान में रखते हुए, यह भी समझदारी है कि एआई कंपनियों को भारत के 1.4 अरब लोगों के डेटा तक जो पहुंच है, उस पर विचार किया जाए और इस बात पर भी कि इतना बड़ा डेटा भंडार अगर गलत हाथों में चला जाए तो कितना खतरा हो सकता है। आधार के विपरीत, जिसे भारत की अपनी संस्थाओं ने विकसित किया था, ज्यादातर बैसिक LLMs अमेरिकी (OpenAI का ChatGPT), फ्रांसीसी (Claude AI) और चीन की कंपनियों के मालिकाना हक में हैं। जब हमारे नागरिकों की निजी डिजिटल जिंदगी-जैसे उनका स्वास्थ्य, आदतें, भाषा और आजीवनिक-विदेशी एआई सिस्टम द्वारा, जो हमारे नियामक नियंत्रण से बाहर हैं, प्रोसेस और उससे कमाई की जाती है, तो संप्रभुता का मतलब नया हो जाता है। हमने यह फेसबुक और एक्स के मामले में देखा है। एआई में नेतृत्व के लिए स्वदेशी LLMs और तकनीकी ढांचे की जरूरत है। डेटा, जमीन और पानी की तरह, अब एक राष्ट्रीय संसाधन है, जिसे सुरक्षित रखना, नियंत्रित करना और जनता के हित में यूज करना जरूरी है। हालांकि, भारत की चुनौती यह नहीं है कि वह ग्लोबल इनोवेशन से पीछे हट जाए, बल्कि उसके

साथ बराबरी की शर्तों पर जुड़ना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारतीय जीवन से ट्रेन किया गया एआई आखिरकार भारतीय लोगों के लिए, भारतीय लोगों द्वारा, और भारतीय लोगों का हो। भारत को अपना खुद का एआई स्टैक बनाना चाहिए, और इसके लिए स्पष्ट guardrails (सुरक्षा नियम) की जरूरत है- संप्रभुता, localisation और accountability पर। इसके लिए सार्वजनिक डिजिटल ढांचे और डिजिटल निगरानी का समर्थन चाहिए, ताकि भारत नवाचार में दुनिया के साथ एक रणनीतिक भागीदार के रूप में जुड़ सके। जैसा कि ऑवेल की 1984 ने चेतावनी दी थी कि एक ऐसी दुनिया होगी जहां शक्ति उन लोगों के पास होगी जो जानकारी को नियंत्रित करते हैं, एआई के युग में यह सवाल उठता है: हमारे जीवन को परिभाषित करने वाले डेटा का मालिक कौन है? जब डिजिटल जिंदगी का टकराव व्यापार से होता है, तो स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिना डेटा के सामने कमजोर हो सकती है।

इस पृष्ठभूमि में, भारत ने अपना आत्मनिर्भर एआई प्लेटफॉर्म Sarvam एआई डेवलप किया है और शुरुआती रिपोर्ट अच्छी हैं। 'भारत के लिए खास तौर पर एआई सिस्टम बनाने के विज्ञान के साथ, Sarvam एआई एक ऐसा संगठन है जो बुनियादी घटकों का निर्माण करके और उन्हें भारत की अनोखी भाषा, एंटरप्राइज और शासन की जरूरतों पर लागू करके भारत के लिए एआई डेवलप कर रहा है।' संगठन अपने मिशन का वर्णन करता है। यह फुल-स्टैक एआई प्लेटफॉर्म पूरी तरह भारत में डिजाइन, विकसित और लागू किया गया है, जो सच में मेक इन इंडिया पहल है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

एनसीईआरटी किताब में 'ज्यूडीशियल करप्शन' पर संग्राम

● चैप्टर पर सीजेआई का ऐक्शन, कहा-बदनाम करने की इजाजत नहीं ● चीफ जस्टिस बोले- यह सोचा-समझा कदम लग रहा, केस खुद देखूंगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' का चैप्टर शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई है। सीजेआई ने कहा- किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में यह मामला सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा-मुझे इसकी पूरी जानकारी है। यह पूरे ज्यूडीशियल इंस्टीट्यूशन के लिए चिंता की बात है। यह सोचा-समझा कदम लग रहा है। मैं किसी को भी, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हों, इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं करने दूंगा। मैं इस मामले पर खुद नोटिस ले रहा हूँ। इंडिया एंड बिगोन पार्ट 2' में 'द रोल ऑफ द ज्यूडीशियरी इन अन्वर सोसायटी' टॉपिक के अंदर ज्यूडीशियरी में करप्शन का टॉपिक जोड़ा है। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी है।



● किताब में पूर्व सीजेआई बीआर गवई का भी जिक्र किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई का भी जिक्र है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि ज्यूडीशियरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामले का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा था, हालांकि, इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज, निर्णायक और ट्रांसपैरेंट एक्शन में है... ट्रांसपैरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक गुण हैं। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस का पार्ट 2 इसी हफ्ते जारी हुआ है। सीजेआई की टिप्पणी के बाद फिलहाल ये किताब एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

● किताब में लिखा, इंसफ में देरी नाइसाफी की तरह है- सोशल साइंस की इस किताब में लिखा गया है- इंसफ में देरी नाइसाफी की तरह है। यहां सुप्रीम कोर्ट में 81 हजार, हाईकोर्ट्स में 62 लाख 40 हजार, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के 4 करोड़ 70 लाख पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक एम सिंघवी ने सीजेआई की बेंच के सामने कहा- बच्चों को ज्यूडीशियरी में करप्शन का सोनेवट ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे यह कहीं और, किसी और इंस्टीट्यूशन में है ही नहीं। यह चिंता का विषय है। हम यहां बार काउंसिल की चिंता लेकर आए हैं। दोनो वकीलों ने कहा, किताब में यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स वगैरह को छोड़ दिया है। दूसरे सेक्टर पर एक शब्द भी नहीं। वे ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे यह सिर्फ इसी इंस्टीट्यूशन में है। जबकि सीजेआई ने कहा, प्लीज थोड़ा इंतजार करें। मुझे बार और बेंच दोनों से बहुत सारे कॉल, मैसेज आ रहे हैं। सभी हाईकोर्ट के जज समेत सिस्टम का हर स्टेकहोल्डर परेशान है। मैं इस मामले को खुद देखूंगा। कानून अपना काम करेगा। बेंच में शामिल जस्टिस बागची ने भी कहा कि यह किताब बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ लगती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मिशन क्षमतावर्धन कार्यशाला का किया शुभारंभ

आजीविका मिशन की दीदियाँ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कर रही हैं सशक्त

40 साल बाद बाहर जाएगी नक्सली संगठन की कमान

● माओवाद के तेलंगाना युग का अंत, एक साल में ढेर हुए 10 टॉप कमांडर



रायपुर (एजेंसी)। माओवादी संगठन में पहली बार तेलंगाना कैडर से बाहर नेतृत्व जाने की संभावना है। थिफिरी तिरुपति उर्फ देवजी और मल्लाली रेड्डी उर्फसंग्राम के समर्पण के बाद संगठन में नेतृत्व का संकट गहरा गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये दोनों शीर्ष माओवादी तेलंगाना पुलिस की हिरासत में हैं। देवजी के समर्पण से तेलंगाना कैडर का वह दबदबा खत्म हो रहा है, जो करीब 40 सालों से माओवादी हिंसा की दिशा तय कर रहा था। अब संगठन की कमान मिशिर बेसरा के हाथों में जाने की आशांका है। देवजी माओवादी संगठन के हिंसक दल का प्रमुख था और अनौपचारिक रूप से भाकपा (माओवादी) के महासचिव की भूमिका निभा रहा था। उसके समर्पण से तेलंगाना कैडर का वह चरित्र समाप्त हो गया है, जो पिछले चार दशकों से था।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आजीविका मिशन से जुड़ी दीदियाँ एकता की शक्ति का सजीव उदाहरण है। बहनों द्वारा एकजुटता से किए जा रहे प्रयास 'बंद मुझे लाख की' के भाव को चरितार्थ करते हुए देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बहनें आज ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन तक चलाने के साथ गैस और पेट्रोल रिफिलिंग जैसे कार्य भी कर रही हैं। कैफे संचालन से लेकर मार्केट का टारगेट पूरा करने में अक्ल बहनें अचर, पापड़ निर्माण सहित कई छोटे उद्योगों से बेहतर कमाई कर रही हैं। भारतीय संस्कृति में मातृ सत्ता का विशेष महत्व है। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश की बहनें सशक्त हो रही हैं। प्रदेश के 5 लाख स्व-सहायता समूहों से 65 लाख से अधिक दीदियाँ जुड़कर सशक्त हुई हैं। इनमें से 12 लाख से अधिक दीदियाँ लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य सरकार प्रदेश की बहनों के सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व-सहायता समूहों ने एक वर्ष में विभिन्न कंपनी और मेलों के माध्यम से 310 करोड़ रुपए का व्यापार किया है। मध्यप्रदेश,



देश का सर्वाधिक प्राकृतिक खेती वाला राज्य है। हमारे स्व-सहायता समूहों की 50 हजार बहनें प्राकृतिक खेती में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में महिला बाल विकास विभाग में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। साथ ही बजट का कुल 34 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को कुशाभाऊ ठककर सभागार में स्वसहायता समूहों की आजीविका मिशन क्षमतावर्धन कार्यशाला का शुभारंभ कर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, कौशल विकास मंत्री श्री गौतम देववाल और पंचायत और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह उपस्थित थीं।

झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पोते की मौत

दवा खाने के बाद मुंह से निकला झाग, पुलिस जांच में खुले कई राज

मनाली (एजेंसी)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच में कई राज खुले हैं। वीर दोस्तों के साथ चार दिन पहले मनाली पहुंचा था। चर्चा थी कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने से उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। वीर सोरेन की मंगलवार सुबह तबीयत ठीक नहीं थी। इस कारण वह दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया था और होम स्ट्रे में ही रहा। दोपहर को दोस्त लौटे तो वीर ने सिरदर्द होने की बात बताई थी। दोस्तों ने उसे ऑनलाइन दवाई मंगवाई, जिसे खाने के बाद उसकी मौत हो गई।

हेलीकॉप्टर में चम्पाई सोरेन, पोस्टमार्टम से किया मना- वीर सोरेन के दादा पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन भी मनाली पहुंचे। उन्होंने शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। उन्होंने पोते का शव घर ले जाने की इच्छा जताई है। दोपहर को स्वजन शव लेकर चले गए। पूर्व सीएम किराये के हेलीकॉप्टर में मनाली पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर में ही शव लेकर खाना हो गया। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि वीर के शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए -मामलों की जांच कर रही है।

रीवा में रावण की 60 साल पुरानी प्रतिमा पर टकराव

एक पक्ष बोला- विकास रुका, अशुभ है, हटाओ, दूसरे ने कहा- विद्वान था, खरोंच नहीं आने देंगे

रीवा (नप्र)। विंध्य की धरती पर इन दिनों आस्था और मान्यता के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। टकराव का कारण रीवा जिले के ल्योथर में करीब 60 साल पुरानी रावण की 10 फीट की प्रतिमा है। एक पक्ष का दावा है कि यह प्रतिमा दोष, बीमारी और विकास में बाधा का कारण है, इसलिए इसे हटा दिया जाना चाहिए। ज्योतिषी और धर्मगुरु इसे वास्तु दोष की वजह बता रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष लंका के राजा रावण की विद्वता का प्रतीक मानते हुए प्रतिमा को खरोंच तक नहीं आने देने की चेतावनी दे रहा है।



पहले पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने कुछ लोगों के सहयोग से इसे स्थापित किया था। इतने सालों तक दशहरा पर सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में इसे मानते आ रहे हैं। समय के साथ क्षेत्र की पहचान रावण की प्रतिमा ही बन गई।

6 महीने पहले बीमारी फैली तो बनी टकराव की स्थिति- करीब 6 महीने पहले क्षेत्र में बीमारी फैली। यहां बड़े से लेकर बच्चे तक बुखार, थायरॉइड, चर्म रोग से पीड़ित हो गए। कुछ को कैंसर डिटैक्ट हुए। ज्यादातर बच्चे मौसमी बीमारी की चपेट में थे। कुछ लोग रीवा आकर बस गए। क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा है, ऐसे में बीमारी से लेकर विकास कार्यों के ठप होने को लेकर कुछ ग्रामीणों ने रावण की प्रतिमा को ही अशुभ संकेत से जोड़ना शुरू कर दिया।

पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने लगवाई थी प्रतिमा- ल्योथर के बीचों-बीच दशानन मैदान में रावण की प्रतिमा स्थापित है। बेटे हुए रावण की यह प्रतिमा काफी बड़ी है। लोगों के अनुसार- करीब 6 दशक

की दृष्टि से काफी पिछड़ा है, ऐसे में बीमारी से लेकर विकास कार्यों के ठप होने को लेकर कुछ ग्रामीणों ने रावण की प्रतिमा को ही अशुभ संकेत से जोड़ना शुरू कर दिया।

subhassaverenews@gmail.com
facebook.com/subhassaverenews
www.subhassavere.news
twitter.com/subhassaverenews

शरद की सुबह

करके फांके गुजर गया कोई
और खा-खा के मर गया कोई।
चलते चलते मेरे घर के आगे
एक पल क्यों ठहर गया कोई।
घर में, बाहर भी बस अंधेरा था
दीप देहरी पे धर गया कोई।
मैं खड़ा देखता था मेले में
इधर आया उधर गया कोई।
रोज मंजर यहाँ बदलते हैं
कोई सँवरा बिखर गया कोई।
वाक्ये भी अजब गुजरते हैं
किसका चारा था चर गया कोई।
बस सियासत का बोलबाला है
है बचा गाँव न शहर कोई।

- दिनेश मालवीय 'अश्क'



4 लाख 42 हजार से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये कराया पंजीयन

भोपाल (नप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अब तक 4 लाख 42 हजार 288 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। किसान 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि निर्धारित समय में पंजीयन जरूर करा लें। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। कुल 3186 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रुपये अधिक है।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि अभी तक इंदौर संभाग में 54 हजार 587, उज्जैन में एक लाख 48 हजार 905, ग्वालियर में 9695, चम्बल में 4692, जबलपुर में 39 हजार 885, नर्मदापुरम में 34 हजार 181, भोपाल में एक लाख 9 हजार 134, रीवा में 13 हजार 260, शहडोल में 2551 और सागर में 25 हजार 398 किसानों ने पंजीयन कराया है।

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है।

प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, अस्पताल बंद मिला

गेट पर जन्मा बच्चा, परिजनों का आरोप- डॉक्टर, नर्स नहीं थे, डॉक्टर सहित तीन को नोटिस

खरगोन (नप्र)। खरगोन में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर जब अस्पताल ले जाया गया तो वह बंद मिला। प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला का मजबूरी में अस्पताल के बाहर गेट पर प्रसव कराना पड़ा। यह मामला बुधवार सुबह 6 बजे झिरिया ब्लॉक के आभापुरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। इसकी जानकारी सुबह प्रशासन को लगी तो अफरा तफरी मच गई। अब अधिकारी अपने बचाव में सफाई दे रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि जब वे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, उस समय वहां कोई भी डॉक्टर, नर्स या अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं था। परिजन रवींद्र भूरिया ने बताया कि स्टाफ के अभाव में महिला को तत्काल इलाज नहीं मिल सका। इसी दौरान महिला को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और मजबूरी में स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही प्रसव कराना पड़ा। कुछ समय बाद स्थानीय लोगों की मदद से महिला और नवजात को संभाला गया।

घटना से नाराज परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि समय पर स्टाफ मौजूद होता तो महिला को सुरक्षित रूप से अंदर भर्ती कर प्रसव कराया जा सकता था। परिजनों ने मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।

सीएमएचओ बोले- परिजन समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे

मामले में खरगोन जिले के सीएमएचओ डॉ. डीएस चौहान ने बताया कि उन्हें स्वास्थ्य केंद्र के बाहर प्रसव की जानकारी मिली है। उनके अनुसार, महिला को फुल टाइम प्रसव पीड़ा चल रही थी और परिजन उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाए।

सीएमएचओ ने यह भी स्पष्ट किया कि घटना के बावजूद जन्मा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। फिलहाल, महिला और नवजात की देखरेख की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।



मथुरा (एजेंसी)। मथुरा के बरसाना में बुधवार को प्रसिद्ध लट्ठमार होली खेली जा रही है। सुबह से ही बरसाना की गलियों भक्तों से सजी-धजी हैं। हर तरफ अबीर-गुलाल दिखाई दे रहा है। गुलाल से रंगे भक्त ढोल-नगाड़ों की धुन पर झूम रहे हैं। डॉस कर रहे हैं। होली के गीत गा रहे हैं। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसवालों के साथ महिलाओं ने लट्ठमार की। नंदगांव

सखियों ने पुलिसवालों को मारे लट्ठ, होली की धूम

मथुरा के बरसाना में लट्ठमार होली में ढोल-नगाड़ों पर डांस

से आने वाले हुरियारों के स्वागत की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं। बरसाना पीली पोखर पर स्वागत के लिए 2000 किलो टंडाई बनाई गई है। होली देखने और खेलने के लिए 20 लाख श्रद्धालु बरसाना पहुंचे हैं। इनमें विदेशी टूरिस्ट भी शामिल हैं। प्रशासन के मुताबिक, सुरक्षा के लिहाज से 4500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और एंटी रोमियो टीम तैनात की गई है। इससे पहले मंगलवार को राधारानी (लाइलीजी) मंदिर में लट्ठमार होली खेली गई थी। महलों ने मंदिर की छत पर बनी सफेद छतरी से लट्ठ लुटाए थे। बरसाना राधा रानी का जन्मस्थान है। लट्ठमार होली में नंदगांव यानी श्रीकृष्ण का जहां बचपन बीता, वहां के हुरियारों 8 किमी दूर बरसाना में होली खेलने आते हैं। कुंज और रंगीली

गलियों से होते हुए करीब 3 किमी तक चलते हैं। गलियों में दोनों तरफ खड़ी हुरियारने लाठियां मारती हैं, इनसे बचने के लिए हुरियारों ढाल का सहारा लेते हैं। ऐसी मनोरम और वर्ल्ड फेमस होली देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट मथुरा-वृंदावन पहुंचते हैं। नंदगांव से आए हुरियारों ने बताया- बस पगड़ी बंध जाए, हम होली खेलने के लिए तैयार हैं। ढाल पूरी तैयार है। इसमें हुरियारी लट्ठ मारेंगी। और हम लट्ठ खाने के लिए तैयार हैं। राधा रानी के दर्शन करके रंगीली गली में होली खेलेंगे। मनीष गोस्वामी नंदबाबा मुख्

पुजारी ने बताया- ये परंपरा ठाकुर जी के समय से चली आ रही है। जो मेरे हाथ में ध्वजा दिख रहा है आपको, ये स्वयं कृष्ण-बलराम का रूप है। नंदगांव से आशीर्वाद लेकर नंदमहल से निकले। ठाकुर जी का हाथ छुआकर। ऐसे ही रास्ते में चलते चले आए। फिर राधा-रानी के स्मृति पहुंचे पीली पोखर। यहां अब हमारा टंडाई-पान-भोग हो रहा है। ये तीन पग वाली जो पगड़ी दिख रही है ये बहुत प्राचीन परंपरा है। ठाकुर जी, जो मुकुट धारण करते हैं रास के समय आते हैं तो बिना पाग के नहीं आते। वहीं परंपरा चली आ रही है। ये स्वयं कृष्ण भगवान हैं हमारे। अभी हम इसे किसी को छूने नहीं देते। सबसे पहले ये श्रीजी के चरणों के पास ले जाएंगे। श्रीजी से स्पर्श कराएंगे। वहां समाज गायन होगा। उसके बाद रंगीली गली में लट्ठमार होली खेली गई।

चार राज्यों के 5407 गांवों के लिए सरकार की सौगात

मोदी कैबिनेट ने 9072 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट किए मंजूर

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को नए कार्यालय सेवा तीर्थ में हुई बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की अनुमानित 9072 करोड़ रुपये की इन तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें गोंदिया-जबलपुर दोहरीकरण, पुनारख-किजल तीसरी और चौथी लाइन तथा गम्हरिया-चांडिल तीसरी तथा चौथी लाइन शामिल है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों से गुजरने वाली इन



परियोजनाओं पर काम पूरा होने के बाद देश में रेलवे का मौजूदा नेटवर्क 307 किलोमीटर बढ़ जाएगा। अरविनी वैष्णव ने

बताया कि इन प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से 98 लाख की आबादी वाले 5,407 गांवों में रेल संपर्क में सुधारा होगा।

जबलपुर-गोंदिया परियोजना को दी गई स्वीकृति

वैष्णव ने कहा कि ये तीनों रेल परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और देश के प्रमुख रेल कॉरिडोरों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इनमें से पहली प्रमुख परियोजना जबलपुर से गोंदिया रेल लाइन है। उनका कहना था कि यदि हम उत्तर भारत, विशेषकर पूर्वोत्तर के प्रयागराज, वाराणसी (काशी), इसके बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश का रीवा संभाग को देखें तो इन सभी क्षेत्रों से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला पारंपरिक मार्ग जबलपुर से इटारसी, इटारसी से नागपुर और वहां से आगे दक्षिण की ओर जाता है। यह मार्ग लंबा होने के साथ-साथ अत्यधिक व्यस्त भी है।

अमेरिकी संसद में ट्रम्प बोले- भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाई

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह संसद में भाषण दिया। साल की शुरुआत में संसद में प्रेसिडेंट के भाषण को 'स्टेट ऑफ द यूनियन' स्पीच कहा जाता है। ट्रम्प ने 1 घंटा 50 मिनट के भाषण में एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। ट्रम्प यह बात 100 से ज्यादा बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु जंग में 3.5 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका थी। हालांकि, भारत इस दावे को हमेशा खारिज करता आया है। अपने भाषण में ट्रम्प ने इजराइल-हमास के बीच गाजा सीजफायर को अपनी उपलब्धि कहा।

हिंदुत्व खतरे में है, सिर्फ ड्रेस पहनकर खुद को हिंदू बता रहे

शंकराचार्य बोले-हिंदुत्व को हिंदुओं के बीच घुसे ऐसे लोगों से है खतरा

वाराणसी (एजेंसी)। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस पिछले तीन दिनों से वाराणसी में डेरा डाले हुए है। पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, हालांकि अभी तक आश्रम नहीं पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक, प्रयागराज पुलिस फिलहाल शंकराचार्य से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है। मामला हाई-प्रोफाइल होने के कारण पुलिस फूक-फूककर कदम आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि पूरी तैयारी और होमवर्क के बाद ही पुलिस शंकराचार्य या उनके शिष्यों से पूछताछ करेगी। उधर, बुधवार को शंकराचार्य ने एक बार फिर मीडिया से बात की।

उन्होंने कहा, हिंदुत्व खतरे में है। जब केवल ड्रेस पहनकर लोग खुद को हिंदू बताते लगे तो बार-बार हिंदू-हिंदू कहेंगे, तो हिंदू को खतरा होना स्वाभाविक है। हिंदुत्व को हिंदुओं के बीच घुसे हुए ऐसे लोगों से खतरा है, जो वास्तव में हिंदू नहीं हैं, बल्कि दिखावे के लिए खुद को हिंदू बताते हैं। उन्होंने कहा, एक-डेड महाने से कहा जा रहा है कि और भी छात्रों का यौन शोषण हुआ है। अगर ऐसा है तो बाकी लोगों को क्यों बचाकर रखा गया है। यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है और सिर्फ दो लोगों से मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो इससे पता चलता है कि इसके पीछे साजिश है। जब उन्हें मुफ्त होगा, तब उन्हें पेश किया जाएगा।



शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से धक्का-मुक्की

वाराणसी (एजेंसी)। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। काशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शंखनाद कर सरकार को चेतावनी दी। पुलिस कार्रमियों से धक्का-मुक्की करते हुए कार्यकर्ता डीएम ऑफिस तक पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य के पोस्टर लहराए, जबकि लखनऊ में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मेरठ, बुलंदशहर, गोरखपुर और ललितपुर सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा।

सीएम योगी के जापान दौरे में मिले मेगा निवेश प्रस्ताव

पहले दिन 11 हजार करोड़ रुपये का एमओयू हुआ साइन

कुबोता व मिंडा सहित कई जापानी कंपनियों ने किए करार

नई दिल्ली/लखनऊ (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन औद्योगिक निवेश को लेकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित हुई है। विभिन्न जापानी कंपनियों के साथ लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। जिन कंपनियों के साथ करार हुआ है उनमें कुबोता कारपोरेशन, मिंडा कारपोरेशन, जापान एविपेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नागासे एंड कंपनी लिमिटेड, सीको एडवांस, ओएंडओ ग्रुप, फूजी जैपनीज जेवी और फूजीसिल्वरटेक कंक्रैट प्रॉलि शामिल हैं। ये समझौते कृषि यंत्र निर्माण, औद्योगिक मशीनरी निर्माण, जल और पर्यावरण अवसंरचना समाधान, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक प्रिंटिंग एवं ग्राफिक्स, हॉस्पिटैलिटी और रिजल एस्टेट

जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं। इससे विनिर्माण क्षमता के विस्तार और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। कुबोता कारपोरेशन, वर्ष 1890 में स्थापित जापान की एक अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और जिसका मुख्यालय ओसाका में स्थित है। यह कृषि और औद्योगिक मशीनरी निर्माण में वैश्विक पहचान रखती है। कंपनी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इंजन और निर्माण उपकरण के साथ साथ जल और पर्यावरण अवसंरचना समाधान जैसे पाइप, पंप और ट्रीटमेंट सिस्टम के क्षेत्र में भी कार्यरत है। एस्कॉर्ट्स कुबोता लिमिटेड के साथ सहयोग के माध्यम से कंपनी भारत में अपने विनिर्माण विस्तार और फार्म मैकेनाइजेशन क्षेत्र में उपस्थिति को मजबूत कर रही है।



एडवांस कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा- नागासे एंड कंपनी लिमिटेड, एक विविधोक्त जापानी ट्रेडिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी है जो केमिकल्स, एडवांस मैटेरियल्स, मोबिलिटी सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सक्रिय है। इन कंपनियों के बीच सहयोग से ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। सीको एडवांस जापान मूल की कंपनी है जो उच्च प्रदर्शन स्क्रीन प्रिंटिंग इंक और कोटिंग सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। इसके उत्पाद ऑटोमोटिव डीकल्स, इंडस्ट्रियल ग्राफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल, ग्लास प्रिंटिंग और कंज्यूमर अप्लायंसेज में उपयोग होते हैं। कंपनी भारत में अपनी विनिर्माण इकाई के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को आपूर्ति कर रही है। इसके अतिरिक्त ओ एंड ओ ने हॉस्पिटैलिटी और रिजल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को लेकर समझौता किया। पहले दिन हुए इन समझौतों को भारत और जापान के बीच औद्योगिक सहयोग को नई गति देने वाला कदम है।

प्रमोद भार्गव को मिलेगा सूरतगढ़ में लक्ष्मणराम सेवटा स्मृति कथा सम्मान

शिवपुरी। भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला एवं सामाजिक जागरण को समर्पित संस्था विविधा, सूरतगढ़ राजस्कीयान की ओर से प्रतियोगिताएं दिए जाने वाले सम्मानों की घोषणा की गई है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. एनके सोमानी ने बताया कि साल 2024-25 के लिए स्व. श्री लक्ष्मण राम सेवटा स्मृति कथा सम्मान प्रमोद भार्गव (शिवपुरी मध्यप्रदेश) को उनके कथा संग्रह 'प्रमोद भार्गव' के साथ अन्याय हुआ है और सिर्फ दो लोगों से मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो इससे पता चलता है कि इसके पीछे साजिश है। जब उन्हें मुफ्त होगा, तब उन्हें पेश किया जाएगा।



श्रीफल भेंट लिए जाएंगे। प्रमोद भार्गव के अलावा कृष्णा देवी कामरा स्मृति हिंदी कविता सम्मान डॉ. प्रभा मुजुमदार (गुजरात) को उनके कविता संग्रह 'नकारती हूं निवासन' पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थानी कविता के क्षेत्र में दिया जाने वाला श्रीमती गोपी देवी चांडक स्मृति सम्मान चांदकौर जोशी (जोधपुर)

को उनके कविता संग्रह 'बिलखता बादल' को, जुगल किशोर सोमानी स्मृति व्यंग्य पुरस्कार वरिष्ठ व्यंग्यकार अखिलेश श्रवास्तव (लखनऊ) को उनके व्यंग्य संग्रह 'दपत्तरनामा' पर दिया जाएगा। उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाने वाला भेरूदान सोमानी स्मृति उपन्यास पुरस्कार अलंकार रसगोपी (लखनऊ) को उनके उपन्यास 'पंडित भया न कोई' तथा अर्जुन राम सुथार स्मृति प्रथम प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार डॉ. नेहल शाह (भोपाल) को उनकी पहली कविता पुस्तक 'और इन सब के बीच' पर दिया जाएगा। संस्था के सचिव संजय कामरा ने चर्चित साहित्यकारों को बधाई दी और कहा कि सभी साहित्यकारों को मार्च माह के अंत तक आयोजित होने वाले भव्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

मप्र में ओले-बारिश, फसलों पर असर

20 जिलों में बिगड़ा मौसम; मार्च की शुरुआत में भी गिरा पानी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ के असर से मौसम बदला हुआ है। पिछले दो दिनों में प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई है। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं, जिससे गेहूँ और चने की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन मार्च की शुरुआत में एक बार फिर बारिश हो सकती है। मंगलवार को छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, पांडुरा, रतलाम, उज्जैन, बालाघाट, मंडला, खंडवा, सीहोर, रायसेन, इंदौर, अनुपपुर और डिंडोरी सहित कई जिलों में मौसम बिगड़ा रहा। कहीं तेज आंधी के साथ बारिश हुई तो कहीं ओलावृष्टि दर्ज की गई।



24 घंटे के दौरान इन जिलों में भी बारिश हुई- इससे पहले 24 घंटे के दौरान श्यांपुर, शिवपुर, ग्वालियर, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, दमोह, जबलपुर, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश दर्ज की गई। शिवपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, मैहर, सीधी और सिंगरौली जिलों में ओलावृष्टि हुई।

27 फरवरी से नया सिस्टम, प्रदेश में भी असर- मौसम विभाग के अनुसार, 27 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) प्रभावित कर सकता है। जिसका असर एमपी में भी देखने को मिलेगा। यानी, 1 और 2 मार्च को प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है।

ठंड का असर नहीं, चलने लगे पखें- इन दिनों उन जिलों में दिन के तापमान में गिरावट हुई है, जहां बारिश का दौर है, लेकिन बाकी जिलों में पारा 30 डिग्री के पार चल रहा है। दूसरी ओर, रात में भी ठंड का असर देखने को नहीं मिल रहा है। सोमवार-मंगलवार की रात में प्रदेश के 5 बड़े शहरों में तापमान 14 डिग्री से ज्यादा ही रहा। वहीं, पचमढी सबसे ठंडा दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री तक रहा। मंदसौर में 10.9 डिग्री, शाजापुर में 11.5 डिग्री, चित्रकूट में 11.7 डिग्री, राजगढ़ में 12 डिग्री, खजुराहो में 12.2 डिग्री, दतिया में 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रायसेन जिले का

निकला सेक्सरैकेट का आरोपी चंदन यादव

● भोपाल आया तो स्या सेंटर में किया काम, 3 साल अमरीन के साथ लिवइन में रहा

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 2 युवतियों से रेप और धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी चंदन रायसेन जिले में बाड़ी बरेली का रहने वाला है। पुछताछ में उसने पुलिस को बताया कि भोपाल आने से पहले छोट-मोटे काम करता था।

सबसे पहले एक शोरूम में काम किया। फिर शाहपुरा और चूनाभट्टी क्षेत्र के एक स्या में नौकरी करने लगा। वह करीब तीन साल तक मुख्य आरोपी अमरीन के साथ लिव-इन रहा था। दूसरी ओर, फरार आरोपी बिलाल, चानू और यासिर की पुलिस टीम तलाश में जुटी है।



‘बड़े लोगों’ से संबंधों के दावे की भी जांच

दोनों पीड़िताओं ने पुलिस को आरोपियों के बड़े लोगों से संबंधों की बात कही है। ऐसे में पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच कर रही है। आरोपियों की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट, डिजिटल चैट और जब मोबाइल की जांच की जा रही है। हालांकि, अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। अफसरों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस संबंध में आधिकारिक जानकारी दी जाएगी।

आरोपी पक्ष के घर वाले सामने आए

पुलिस के अनुसार आरोपियों के घर वाले सामने आए हैं। उन्होंने प्रारंभिक बातचीत में बताया कि उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि, अब तक आरोपियों के परिवार की ओर से केवल एक युवक ही सामने आया है। पुलिस उससे भी पुछताछ कर तथ्य स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है।

मदद और काम दिलाने के नाम पर संपर्क किया

भोपाल और छत्तीसगढ़ की दो युवतियां 22 फरवरी को रात में बाग सेवनिया थाने पहुंची थीं। दोनों ने अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि अमरीन और आफरिन ने पहले मदद और काम दिलाने के नाम पर संपर्क किया, फिर हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल का झांसा देकर पार्टियों में ले जाना शुरू किया। पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ जबर्न शारीरिक संबंध बनाए गए और धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 31 दिसंबर 2024 को शाहपुरा स्थित एक होटल में दोस्त की बर्थडे पार्टी में उसकी मुलाकात अमरीन से हुई। बाद में दोनों साथ रहने लगीं। जनवरी 2025 में वे बागसेवनिया में रहने वाली अमरीन उर्फ माहिरा के पास शिफ्ट हो गईं। कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि उसकी सहेली ने अमरीन के कहने पर धर्म परिवर्तन कर उसके भाई से शादी कर ली है। इसकी लत लगाने के आरोप भी पीड़िता ने लगाए हैं।

विधानसभा में बजट सत्र का आठवां दिन

कांग्रेस बोली- सीएम, मंत्री के झगड़े में मास्टर प्लान अटका

सिंगरौली में अदाणी माइंस के लिए काट रहे पेड़; मंत्री का जवाब- इससे नुकसान नहीं

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आठवां दिन निराश्रित गोवंश, अदाणी कोल माइंस, मास्टर प्लान और टूटते पुलों को लेकर हंगामे के नाम रहा। कांग्रेस विधायकों ने कोल माइंस के लिए पेड़ कटाई को गैर जरूरी बताया तो भाजपा की तरफ से कहा गया कि पेड़ कटाई से कोई नुकसान नहीं होगा।

कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा- ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री कह रहा है कि हमने मास्टर प्लान बना लिया, मुख्यमंत्री जी को दे दिया। अब मुख्यमंत्री जी के यहां रुका हुआ है। इन दोनों के झगड़े में इंदौर जैसे ऐतिहासिक शहर का मास्टर प्लान अटका हुआ है।

तराना विधायक महेश परमार बोले- जब से राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री बने हैं, तब से पुल टूटने के मामले में रिकॉर्ड बन रहा है। भोपाल में 90 डिग्री एंगल का ब्रिज बना दिया और मंत्री जी कह रहे हैं कि देश में ऐसे कई और पुल बने हुए हैं। यदि यह पुल सही बना था तो उन अधिकारियों को प्रोत्साहित क्यों नहीं किया? उनके ऊपर कारवाही करके उन्हें सस्पेंड क्यों किया, इसका जवाब दें।

फसल की रखवाली करें या गोवंश को ढूँढते फिरें किसान- कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने निराश्रित गोवंश से फसलें नष्ट होने और यातायात बाधित होने की स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल की रखवाली करें या निराश्रित गोवंश को ढूँढते फिरें। किसान रात में टॉच लेकर खेतों में गोवंश को भगाने को मजबूर हैं। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने कहा कि निराश्रित गोवंश से परेशान होकर किसान अपने खेतों में करंट लगा देते हैं, जिससे अनजाने में गोवंश की मौत हो जाती है। कई बार बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं।

इसके जवाब में पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने



कहा- 25 जिलों में गौशालाओं के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं। जबलपुर, रायसेन, दमोह, सागर, अशोकनगर, खरगोन और रीवा में टेंडर जारी हो चुके हैं। एक स्थान पर कम से कम 5 हजार गोवंश रखने की व्यवस्था होगी। वर्तमान में करीब 10 लाख निराश्रित गोवंश बेसहारा हैं, जिनमें से 4 लाख नई व्यवस्था के बाद सुरक्षित हो सकेंगे।

जंगलों और आदिवासियों को उजाड़ना चाहती है बीजेपी- वहीं, सिंगरौली में अदाणी समूह की कोल माइंस के लिए पेड़ कटाई मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने कहा कि बीजेपी जंगलों और आदिवासियों को उजाड़ना चाहती है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह बोले- भाजपा अदाणी जी के पास गिरवी रखी हुई है। जब भी अदाणी जी पर कांग्रेस के विधायक या नेता कोई आरोप लगाते हैं, तो भाजपा नेताओं को आपत्ति होने लगती है।

इसके जवाब में भाजपा विधायक रामनिवास शाह

ने कहा- पेड़ कटाई से सिंगरौली का एक पैसा का नुकसान नहीं होगा। कोल माइंस के लिए पेड़ काटना जरूरी है, क्योंकि बिना कोयले के बिजली और बिना बिजली के पानी संभव नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि पेड़ कटाई के बजाय विस्थापन और मुआवजे के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। असली समस्या जमीन, विस्थापन और मुआवजे की है, जिस पर सरकार काम कर रही है। अदाणी को खदान मिलने पर उन्होंने कहा कि खदान नीलामी प्रक्रिया से मिलती है और अदाणी के अलावा एस्सार, जेपी और नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड जैसी कंपनियां भी वहां काम कर रही हैं।

पूर्व मंत्री बोले- भोपाल मेट्रो को रायसेन और सांची से जोड़ा जाए- लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु राम चौधरी ने सदन में कहा कि भोपाल से चलने वाली मेट्रो को रायसेन और सांची से जोड़ा जाए। ये पर्यटन स्थल हैं, इससे मेट्रो में यात्री बढ़ेंगे।

आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, बेहोश होकर गिरी कर्मचारी

ढाई साल का बच्चा भी साथ में, भोपाल के जेपी अस्पताल के बाहर हंगामा, पुलिस-कर्मचारियों में धक्का-मुक्की

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के लगभग 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी रेगुलराइजेशन समेत 9-सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 फरवरी 2026 से शुरू हुआ यह प्रदेशव्यापी आंदोलन भोपाल में ‘न्याय यात्रा’ और सामूहिक हड़ताल के साथ तेज हो गया है। इससे जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल परिसर में करीब 3 हजार कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर बैरिकेडिंग कर दी गई। सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी गेट पर ही नारेबाजी कर रहे हैं।

महिला कर्मचारी बेहोश होकर गिरी, ढाई साल के बच्चे साथ प्रदर्शन- वहीं जेपी अस्पताल परिसर में कर्मचारियों की न्याय यात्रा में शामिल एक महिला कर्मचारी बेहोश होकर गिर पड़ी। वह अपने ढाई साल के बच्चे के साथ प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची थीं। बच्चे को साथी कर्मचारी संभाल रहे हैं, जबकि मीना को स्वास्थ्य संचालनालय के सामने बने चबूतरे पर लिटाया गया है।

प्रदर्शनकारी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के ऑफिस से मुख्यमंत्री के घर तक न्याय मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें जगह से बाहर जाने से रोक दिया। एड्स कंट्रोल एम्प्लॉइज यूनियन,

जॉइंट डेगू-मलेरिया एम्प्लॉइज यूनियन, ऑल हेल्थ ऑफिसर्स एम्प्लॉइज फेडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स हेल्थ वर्कर्स यूनियन और नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

काली पट्टी बांधकर जता चुके विरोध,

स्वास्थ्य सेवाएं से न्याय यात्रा निकालकर राजधानी में विरोध दर्ज कराया गया है, ताकि उनकी मांगें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंच सकें।

कैसर का खतरा, लेकिन अलाउंस सिर्फ 50 रुपए- मध्य प्रदेश रेडियोलॉजी



कोई ध्यान नहीं दे रहा- समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कौरव ने बताया कि 2 फरवरी से सविदा कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे। इसी वजह से पिछले दो दिनों से कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे थे। उन्होंने कहा कि आज संचालनालय

टेक्नीशियन एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र राजपूत ने कहा कि सरकारी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन को पिछले 35 सालों से रेडिएशन अलाउंस के तौर पर सिर्फ 50 रुपए मिल रहे हैं। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में अलाउंस 1,500 से 2,500 रुपये तक है।

भोपाल में लैब संचालक ने फांसी लगाकर किया सुसाइड



पत्नी से विवाद के बाद नाराज होकर घर से निकले थे, लौटकर दी जान

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोलार इलाके में रहने वाले एक लैब संचालक ने मंगलवार देर रात घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इससे पहले उनका पत्नी से मामूली विवाद हुआ था। नाराज होकर घर से निकले और देर रात घर लौटे, कब उन्होंने खुदकुशी कर ली पत्नी और बच्चों को पता ही नहीं चला। बुधवार तड़के उठी पत्नी ने पति के शव को देखा, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से बोंडी को उतारा और पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। खाने को लेकर हुआ था पत्नी से विवाद- पुलिस के मुताबिक पुष्पेंद्र धीरे धीरे रामलखन दोरे (40) कोलार रोड गिरधर अपार्टमेंट के रहने वाले थे। एक लैब का संचालन करते थे। उनके दो बेटे हैं और दोनों स्कूली छात्र हैं। पुष्पेंद्र ने मंगलवार देर रात को मर्जी का खाना नहीं मिलने की बात पर नाराज हो गए थे। घर कब लौटे किसी को भनक तक नहीं लगी- इस बात को लेकर उनका पत्नी से मामूली विवाद हुआ था। इसके बाद वह घर से चले गए। देर रात को घर लौटे और एक कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बुधवार दोपहर को पीएम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी एंगल पर जांच की जा रही है।

एमपी में घाटे में चल रहे 9 सरकारी कृषि फार्म

● रीवा में 26.91 लाख खेती पर खर्च, आय हुई 1.52 लाख; वजह- मौसम आधारित खेती ● कृषि विकास विभाग के मंत्री एदल सिंह कंसाना ने दी जानकारी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बताने वाली सरकार अपने ही कृषि फार्म में घाटे से उबर नहीं पा रही है। प्रदेश भर में मौजूद 46 कृषि फार्म में से 9 घाटे में हैं। सरकार मानती है कि इन कृषि फार्म से होने वाली घाटे की वजह मौसम आधारित खेती और मौसम की प्रतिकूलता है। कृषि फार्मों में प्राकृतिक और मानव संसाधन की कमी का भी असर घाटे की वजह है।

किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के मंत्री एदल सिंह कंसाना ने यह जानकारी विधायक राजन मंडलोई के सवाल के लिखित जवाब में दी है। उन्होंने कहा है कि खेती करने में उपयोग में आने वाले बीज और अन्य सामान का बाजार मूल्य काफी अधिक होना भी खेती



से होने वाले फायदे पर असर डालता है। घाटे में चलने वाले फार्म की स्थिति का अंदाजा इससे लगता है कि रीवा जिले के जितनी फार्म में वर्ष 2024-25 में 26 लाख 91 हजार रुपए खेती पर खर्च किए गए और आमदनी सिर्फ 1 लाख 52 हजार रुपए की हुई। भोपाल जिले के चांचेड़ फार्म में 42.50 लाख रुपए खेती पर खर्च किए गए और उससे आमदनी सिर्फ 17.85 लाख रुपए की हुई।

ऐसी ही स्थिति अन्य फार्म हाउस के मामले में है। एमपी में घाटे में चलने वाले 9 कृषि फार्म पर पांच साल में 8 करोड़ 99 लाख 86 हजार रुपए खर्च किए गए। इसके विपरीत आमदनी 4 करोड़ 4 लाख 90 हजार रुपए ही हुई।

संपादकीय

भारत की आतंकवाद विरोधी नीति

भारत सरकार ने पहली बार अपनी आतंकवाद विरोधी नीति एवं रणनीति की स्पष्ट व्याख्या की है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ जानकारों के मत में जो झूफट सरकार ने जारी किया है, उसमें नीति जैसा कुछ नहीं है, व्याख्या भर है। बहरहाल, इस आतंकवाद विरोधी नीति को 'प्रहार' (अंग्रेजी में PRAHAAR) नाम दिया गया है। आठ पेज की इस नीति में आतंकी हमलों को रोकने पर खास जोर दिया गया है। साथ ही खतरे के मुताबिक तेज और संतुलित कार्रवाई की बात कही गई है। केंद्र ने नीति की प्रस्तावना में PRAHAAR का फुल फॉर्म बताया है। प्रस्तावना में कहा गया है कि हमारे 'कुछ पड़ोसी देशों ने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के एक अंग के रूप में इस्तेमाल किया है। फिर भी भारत आतंकवाद को किसी खास धर्म, जाति, देश या सभ्यता से जोड़कर नहीं देखता।' नीति में कहा गया कि आतंकी इंटरनेट का इस्तेमाल आपस में संपर्क, संगठन में भर्ती और जिहाद के महिमा मंडन के लिए करते हैं। सरकार ने आतंकवाद को लेकर भारत की भारत की ज़ीरो टॉलरेंस नीति दोहराई है। कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी धार्मिक, जातीय या वैचारिक आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत हर तरह के आतंकवाद की हमेशा कड़ी निंदा करता रहा है। विदेशों की जमीन से काम करते हुए आतंकियों ने भारत में हिंसा फैलाने की साजिशें रची हैं। इनके संचालक (हैडक्वार्टर) ड्रोन समेत नई तकनीकों का इस्तेमाल कर पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और हमलों को अंजाम देने में मदद करते हैं। नीति में आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने के लिए एक व्यवस्थित और खुफिया जानकारी पर आधारित स्ट्रक्चर बनाने और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नीति में यह भी कहा गया है कि आतंकी संगठन अब तेजी से संगठित आपराधिक गिरोहों की मदद ले रहे हैं, ताकि लांजिएटिक सपोर्ट और भर्ती के जरिए भारत में आतंकी हमले कर सकें। प्रचार, आपसी संपर्क, फंडिंग और हमलों को दिशा देने के लिए ये आतंकी समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। 'प्रहार' में सरकार के साथ पूरे समाज की भागीदारी वाला तरीका अपनाने की बात कही गई है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ जैसे हालात को खत्म करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति का मुख्य मकसद भारतीय नागरिकों और देश के हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों को रोकना है। इसके अलावा खतरे के मुताबिक तेज और संतुलित जवाब देना है। नीति में कहा गया है कि आतंक के खिलाफ सरकार के अलावा-अलग विभागों की ताकत को मिलाकर काम करना है। खतरों से निपटने के लिए मानवाधिकार और कानून आधारित प्रक्रियाएं अपनानी हैं। भारत सक्रिय और खुफिया जानकारी पर आधारित रणनीति अपनाता है। इसमें मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) की अहम भूमिका है। इंटरलिंग्वेस ब्यूरो (IB) के तहत काम करने वाली जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटरलिंग्वेस (JTFI) का भी जिक्र है, जो देशभर में रिवाल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त कार्रवाई के लिए काम करते हैं। यूईएस नीति में कई बातें कही गई हैं, लेकिन अक्सर सवाल इस नीति पर प्रभावी अमल की नीयत और तैयारी का है। सरकारी इस पर कितनी ईमानदारी और अखरदार ढंग से अमल करती है, इस पर नीति की सफलता निर्भर है। लेकिन यह नीति उस दिशा में एक ठोस और जरूरी कदम है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। खासकर तब कि जब भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसियों के साथ और भी कई एजेंसियां सक्रिय हैं।

एआई की बुद्धिमत्ता और हमारी मूर्खताएं



नजरिया

अरुण कुमार त्रिपाठी

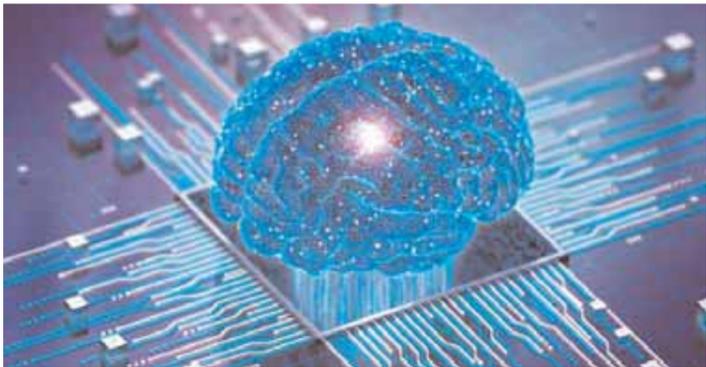
लेखक पत्रकार एवं मीडिया शिक्षक हैं।

भगवती चरण वर्मा की कहानी है 'वसीयत'। उसमें पंडित चूड़ामणि मिश्र के परिवार के लोग जीते जी उनकी उपेक्षा करते हैं लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत धन के लालच में वसीयत पढ़े जाते समय प्रेम और सम्मान का दिखावा करते हैं। जिस उत्तराधिकारी की आलोचना होती है वह कुढ़ता है और जब कुछ मिल जाता है तो वह प्रशंसा करने लगता है। बाद में वसीयत में पंडित तोते के स्वर में अपने शिष्य जनार्दन जोशी से कहते हैं तुम मूर्ख हो और मैं पंडित। कहीं ऐसा न हो कि होमो सेपियन्स की मानव प्रजाति अपने निधन के बाद जो वसीयत छोड़ जाए उसको लेकर उसकी संतानें कुछ वैसा ही नाटक करें और जो नैतिकता की बात करे उसे बुद्ध बता दिया जाए।

इजराइल के मशहूर इतिहासकार युआल नोवा हारी अपनी पुस्तक नेक्सस में कहते हैं कि हमारी प्रजाति बहुत बुद्धिमान है। क्योंकि उसने बेइंतहा तस्की की है। लेकिन वह मूर्ख भी है क्योंकि वह अपने विनाश के उपकरण लगातार जमा करती जा रही है। वे कहते हैं कि जर्मनी ने एक अधिनायकवादी उपकरण खड़ा किया और तकर्रीबन एक करोड़ लोगों की जान ली। आखिर में वह खुद भी धराशायी हो गया। लेकिन अब विनाश के उपकरण सार्वभौमिक हो गए हैं। वे मानव के नियंत्रण से बाहर निकलने को छटपटा रहे हैं। सर्वसत्तावाद सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में पैदा हुई लोकतंत्र की लहर को शांत करता हुआ झूठ, अनैतिकता, सत्तालोलुपता, अफवाह, दुर्भावनापूर्ण सूचनाएं, युद्ध और विनाश के नए औजारों को बांटते हुए नई सृष्टि का सृजन कर रहा है। इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संपन्न सभ्यता नए किस्म की मूर्खताओं की ओर अग्रसर हो रही है।

जो लोग दूसरों को मूर्ख और स्वयं को अधिक बुद्धिमान समझते हैं वे कितने किस्म की मूर्खताएं करते हैं उसकी तमाम कहानियां हमारी लोककथाओं में बिखरी पड़ी हैं। जैसे तीन जगह गंदगी लाने वाली कहानियां। उसकी एक झलक हाल में दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मिट 2026' में दिखाई पड़ी। जो सम्मेलन एआई से जुड़े मानव प्रजाति के गंभीर सवालों पर चर्चा के लिए आयोजित हुआ था और जिस पर भारतीय मीडिया में तमाम पत्रे और घंटे खर्च भी किए वह कूल मिलाकर कुछ नेताओं के अहंकार और कुछ संस्थाओं के झूठ और मूर्खताओं का

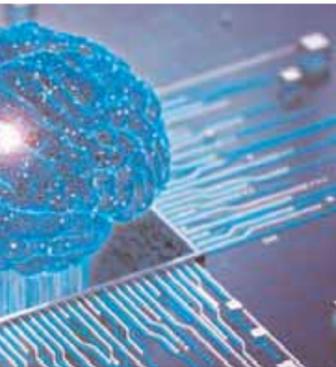
आयोजन बनकर रह गया। संभव है कुछ अच्छी बातें हुई हों और कुछ सवाल उठे हों लेकिन बाहर जो संदेश गया वो यही गया कि ग्लगोटिया विश्वविद्यालय ने ऑरियो (एक कुत्ता) नाम के एक रोबो को अपने केंद्र में विकसित बताकर दर्शाया और उसे आईटी मंत्री ने अपने टिवट पर प्रचारित किया लेकिन बाद में जब चीन और नैटोजन ने यह असलियत उजागर की कि वह तो उनकी यूनीटी नाम की कंपनी ने जीओ 2 नाम से विकसित किया है तो उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। यानी संसार को मूर्ख बनाने चले खुद ही मूर्ख बन गए। फिर तो एपेस्टीन फाइल्स में विवादित माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के भाषण का न होना और बाद में



ओपेन एआई सीईओ सैम आल्टमैन का यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा हाथ जबर्दस्ती पकड़ कर उठा दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इसी तरह की एक घटना उस समय भी हुई जब ओपेन एआई के सीईओ आल्टमैन और एंथ्रोपिक के डायो अमोदेई का हाथ मिलवाने की कोशिश हुई और वे दोनों अपनी मुझे ही बांधे हुए। उन्होंने ऊपर उठा हुआ हाथ एक दूसरे से नहीं मिलाया। वे दोनों कंपनियां एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हैं। पंडित चूड़ामणि मिश्र की संतानों की इस लोभ लालच, पाखंड और फरेब देखकर संदेह होता है कि वे वास्तव में पंडित जी की विरासत के साथ क्या करेंगे। एआई पर होने वाला यह पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नहीं था और न ही भारत ने इसमें कोई विशेष किस्म का नवोन्मेष किया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 'मानव' संबंधों जमले के माध्यम से उन नैतिक सवालों को उठाने की एक हद तक कोशिश की जो पहले उठते रहे हैं। जैसा कि हमारी सरकार हर चीज का लोकलुभावन संधेपीकरण करती है वैसा इस 'मानव' के मामले में भी था। यहां एम का अर्थ माल है, ए से अकाउंटेंटबिलिटी, एन से नेशनल

सावरिनिटी, ए से एक्सेसबल/इनक्लूसिव और वी से वैलड/ लेजिटिमेट का मतलब था। यानी यह सम्मेलन नैतिकता, राष्ट्रीय संप्रभुता, पहुंच, समावेशिता, वैधता पर केंद्रित था।

इस बारे में पहला सम्मेलन ग्रेट ब्रिटेन के ब्लेट्चेली पार्क में 2023 में हुआ था। उसका जोर इस बात पर था कि एआई से पैदा होने वाले खतरे को संभालने के लिए कैसे वैश्विक सहयोग विकसित किया जाए। उसके बाद दूसरा सम्मेलन दक्षिण कोरिया के सिसोल में 2024 में हुआ। उस सम्मेलन में 27 देश इस बात पर राजी हुए कि किस प्रकार एआई से सुरक्षित रहने के लिए एक नेटवर्क बनाया जाए जो



कि मानक निर्धारित करे। तीसरा सम्मेलन पेरिस में 2025 में हुआ जहां पर यह तय किया गया कि किस प्रकार इसके एकाधिकार को रोकने के लिए पाददर्शी एआई आधारभूत ढांचा बनाया जाए। एआई के बारे में जो गंभीर सवाल हैं क्या वे हमारी चिंताओं में हैं या फिर हम अपने को तकनीकी महारुशिकी दर्शाने या महारुशिकियों के साथ खड़े होने की होड़ में उनकी उपेक्षा करते जा रहे हैं?

एआई के तमाम विशेषज्ञों ने जो सवाल और संदेह खड़े किए हैं उन पर हमें विचार करना ही चाहिए और उनके समाधान की दिशा में बढ़ना चाहिए। हमसे पहले ज्योफ्री हिल्टन जिन्हें एआई का जनक कहा जाता है उनकी चिंताओं को देखना चाहिए। हिल्टन ने साफ तौर पर अफसोस जताया है कि काश! मैंने यह आविष्कार न किया होता। यह मानवता के लिए खतरा है। क्योंकि एआई अगले 20 वर्षों में मानव जाति की बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ सकती है। यह शैतानी शक्तियों के हाथों में पड़ सकती है और इससे जैविक हथियार बनाए जाने, बड़े पैमाने पर विस्थापन, बेरोजगारी, सामाजिक अस्थिरता और मानव के नियंत्रण के बाहर होने का खतरा है। इसी तरह की चिंता एक और विशेषज्ञ योशुआ

बेनजिओ ने भी जताई है। उनका कहना है कि इससे विनाशकारी खतरा है।

एआई से जुड़े नैतिक सवाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी उठते रहे हैं। जैसे कि बेरोजगारी, असमानता, मानवता, कृत्रिम मूर्खता, नस्ली रोबो, सुरक्षा, शैतानी शक्तियां, अनियंत्रण की चुनौती और रोबो के अधिकार। अभी एआई के बारे में जो समझाइश दी जा रही है वो यही है कि पहले भी जब नई मशीनें आई थीं तो इसी तरह के तर्क दिए जाते थे कि उनसे मानव का रोजगार छिन जाएगा। लेकिन सभ्यता चली जा रही है और कोई खास दिक्कत नहीं आई। जब एआई मनुष्य ने बनाया है तो वह उसे नियंत्रित करना भी चाहेगा और अगर चाहेगा तो वह नियंत्रित कर लेगा। जो लोग बेरोजगार होंगे वे मानव समाज की सेवा के काम में लगे। एक तरह से मनुष्य के पास रचनात्मक अवकाश होगा। क्योंकि दफ्तरों, शिक्षण संस्थाओं, फैक्टोरियों, सेनाओं के काम को तो एआई संभालने जा रहा है। अगर एआई के माध्यम से ट्रक और गाड़ियां चलाने पर कम दुर्घटनाएं होती हैं तो एआई क्यों बुरा है। इससे तो मानवता सुरक्षित होगी।

लेकिन एआई से पैदा होने वाले खतरों को हम दुनिया में बढ़ते युद्ध और नक्साम्राज्यवाद के खतरों से अलग करके नहीं देख सकते। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 20 जनवरी 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दवांस बैठक में जो बात कही है उस पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना था कि पुरानी विश्व व्यवस्था भीतर से फट गई है। नई विश्व व्यवस्था बननी चाहिए लेकिन वह अभी बन नहीं पाई है। दूसरी ओर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने म्यूनिख के सुरक्षा सम्मेलन में फरवरी में दिए अपने भाषण में कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विओपनिवेशीकरण का दौर चला वह वास्तव में पतन का दौर था। इसलिए अगर हमें पंचम की नई सदी कायम करनी है तो विश्व युद्ध से पूर्व के औपनिवेशिक दौर की प्रसंगिकता के बारे में सोचना चाहिए।

एआई के बढ़ते प्रभाव और हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली स्वचलित नाभिकीय मिसाइलों के आविष्कार की रोशनी में इन इरादों को देखना चाहिए। कुछ विश्लेषक इसे डाटा साम्राज्यवाद के रूप में भी देखते हैं और कुछ एकाधिकारवाद के रूप में भी देखते हैं। भारत में हुए सम्मेलन में इन बड़े सवालों को कितना संबोधित किया गया कहा नहीं जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में भारत विओपनिवेशीकरण का अगुआ था। उसका आजादी से प्रेरित होकर दुनिया के सौ से अधिक देश आजाद हुए थे। क्या आज भारत अपनी उस विरासत को याद रखेगा? या पंडित चूड़ामणि मिश्र की तरह अपनी लालची संतानों को विरासत सौंप कर पूरी मानव जाति के साथ यह कह कर सो जाएगा कि तुम मूर्ख हो और मैं पंडित हूँ।

आरक्षण हटाने की नहीं, उसकी विसंगतियों पर चर्चा हो



मुद्दा

डॉ. गरिमा संजय दुबे

लेखक प्राध्यापक हैं।

यदि आप एक संवेदनशील, न्यायप्रिय मन के व्यक्ति हैं और जमीनी हकीकत को जानते हैं तो आप सामाजिक न्याय की अवधारणा में आरक्षण के महत्व को नकार नहीं देंगे। आरक्षण क्यों आवश्यक था, आज भी क्यों आवश्यक है इस विषय पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए किंतु किसी दुर्भावना के साथ नहीं तथ्य पर आधारित हो।

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण नित्य ही ऐसे कई मामलों से सामना होता है जब लगता है कि आज भी आरक्षण आवश्यक है। लोक कल्याण की योजनाओं पर कार्य करने वाले अधिकारी भी इनसे रोज दो चार होते होंगे, यदि कोई पूर्वाग्रह मन में न हो तो आरक्षण की आवश्यकता पर कोई संशय नहीं होता आज भी।

यह एक बड़ा कटु सत्य है कि सामाजिक विसंगतियों की खाई के चलते यह स्वतंत्रता के पश्चात आरक्षण नहीं होता तो केवल कुछ समुदायों की समृद्धि भारत की समृद्धि नहीं हो पाती। सामाजिक न्याय की अवधारणा में वे भी एन राव रहे हों, अंबेडकर रहे हों या कोई और जो नियम डाले गए वह एक समाज के तौर पर सबके विकास का बीज थे। यदि आरक्षण नहीं होता दलित वंचित पीड़ित कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, आज ही यदि आरक्षण न हो तो कई बच्चे नहीं पढ़ पाएँ, उनकी आर्थिक स्थिति आज भी वैसी नहीं है कि वे विद्यालय महाविद्यालय का शुल्क जमा कर पाएँ, जब दरिद्र इतने रहे तो कि भोजन के लिए ही संघर्ष करना पड़ा तो पुस्तकें कहाँ से आतीं, तो बुद्धि का जो डीएनए विकसित होना चाहिए वह कैसे हो, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था को मिटाने की बात आज भी नहीं की जा सकती, हं उसे न्यायसंगत विसंगति रहित और प्रत्येक वंचित, दरिद्र के लिए लागू कवाने की होनी चाहिए चाहे वह किसी भी जाति समुदाय से आता हो। सरकार की अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएँ इसी आधार पर कार्य कर रही हैं, उनका निरीक्षण सही हो और सही व्यक्ति तक सहायता पहुंचे इसकी और चुस्त व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

उसमें जो विसंगतियाँ हैं, राजनीतिक विकृति और सामाजिक

भ्रष्टाचार ने जो विसंगतियाँ पैदा की हैं आरक्षण की अवधारणा में, उसपर खुल चर्चा होनी चाहिए।

सर्वप्रथम बात आती है भेद की, हमें भेद पर बात करनी चाहिए, जाति पर नहीं। किंतु होता यह रह कि जाति, धर्म पर आधारित भेद को ही एकमात्र सत्य मानकर कुछ जातियाँ सदा पीड़ित मानी गई, कुछ सदा शोषक।

भेद इस सृष्टि में हर कहीं है, इस्लाम सिया, सुन्नी, अहमदिया, यहूदी के भेद से उबरा नहीं है, ईसाई में, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स ओल्ड और न्यू प्रोटेस्टेंट, और उनमें पद के कई भेद हैं, जैन, बुद्ध, इत्यादि सभी में भेद है, जहां कोई और भेद नहीं है वहां काले गेरे का भेद है, अमेरिका और अफ्रीका अभी भी इस भेद में उलझे हैं। भारत में भेद का बहुतायत है, एक जाति सामाजिक संरचना में धर्म, मजहब, जाति, भाषा, रंग, भोजन, पहनाना, परम्पराओं के अनगिनत भेद हैं उन सभी भेद को समाप्त करने की बात होनी चाहिए।

किंतु आरक्षण की विसंगतियों ने जाति प्रमुख भेद ही भेद पीछे रह गया। केवल आरक्षण से भेद कहां समाप्त हुआ, बल्कि बढ़ ही है, आरक्षित अनारक्षित का भेद, इसलिए भेद केवल जातियों के बीच है ऐसा नहीं है और पीड़ित केवल निचली जातियाँ होती हैं ऐसा भी नहीं है। भारत जैसे देश में कौन पीड़ित भेद है, कौन ऐसा है जिसने कभी न कभी किसी न किसी तरह के भेद का सामना नहीं किया। इसलिए भेद मिटे इसकी बात होनी चाहिए, किसी एक जाति विशेष के लिए भेद मिटे, शोष के लिए लागू रहे यह अन्याय होगा। किसी एक जाति के नाम को लेना अपराध और दूजी जाति पर निरंतर आपत्तिजनक शब्दों की बौछार को प्रातिशीलता और न्याय मानना न केवल असंवैधानिक है बल्कि अमानवीय भी।

इसलिए आरक्षण चलता रहे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु उसके आधार पर भेद दृष्टि बंदे और एक हथियार की तरह उसका उपयोग हो इसे रोक जाना चाहिए। भेद को समाप्त कीजिए किसी भी स्तर पर, जाति, धर्म, भाषा, रंग, लिंग, भोजन आधारित भेद किसी के भी साथ ही गलत माना जाए तभी समस्तता की अवधारणा बल पाएगी।

दूसरा आरक्षण के आवंटन में विसंगति और आज भी क्यों वंचित हैं लोग, क्योंकि जिन्होंने आरक्षण ले लिया वे पीड़ितों तक अभी भी आरक्षण ले रहे हैं। किसी वंचित का अधिकार किसी सवर्ण में नहीं मारा है, वह तो अपने पचास प्रतिशत में संघर्ष कर रहा है, उसने देखा ही नहीं कि आपको क्या मिला रहा है, वह अपने

प्रयास बढ़ाता रह।

उसने इसे सामाजिक न्याय की आवश्यकता समझ स्वीकार किया है, विशेष वह अन्याय का करता है। वे जो पीड़ियों से आरक्षण ले रहे हैं अपने ही तबके के लिए आरक्षण नहीं छोड़ पा रहे वह क्रीमी लेयर इस आवंटन में विसंगति को देखे। एक पीढ़ी के बाद आरक्षण नहीं मिलना चाहिए यह नियम उनके ही दलित वंचित पीड़ित भाईयों के लिए सही होगा, वे अपना आरक्षण नहीं छोड़ना चाहते और सवर्णों से द्वेष पाते हैं, सवर्ण इसमें कहां दोषी है।

तीसरा, स्कूल शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान सुविधाएं दी जानी चाहिए चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि और जाति समाज से आते हों, विद्यालय महाविद्यालय समानता सीक्वां के केंद्र हैं, वहीं से बीज गलत पड़ जायेगा तो आगे सुधार कैसे होगा, इसलिए बहुत कुछ सरकार कर रही है जो कुछ थोड़ा बहुत सुधार और है उसमें आरक्षित अनारक्षित सभी को समान सुविधाएं मिलें। आर्थिक स्थिति पर बात होनी चाहिए लेकिन हम जाति पर ही बात करना चाहते हैं। गरीबी की कोई जाति नहीं होती, भूख का कोई धर्म नहीं होता। हर गरीब को सुविधा और हर भूख को भोजन मिले यही सामाजिक न्याय है। क्या भूखे ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय को भोजन का अधिकार नहीं, क्या गरीब ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय सुविधा का अधिकारी नहीं। आरक्षण का विरोध केवल इन्हीं विसंगतियों के कारण है। छत्रवृत्ति का आधार भी यही हो। सरकार ने कई मॉडर्न छत्रवृत्ति चालू कर सामान्य मेधावी, EWS के लिए व्यवस्था की है जो कुछ कुछ सहारा बनी है यह अच्छी पहल है, ऐसे और अवसर तैयार किए जाने चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की फस निर्धारण में सरकार सीधा हस्तक्षेप कर ही सकती है, सब पढ़े सब बढ़ें में जाति आधारित परीक्षा शुल्क, फॉर्म भरने की फीस की विसंगतियाँ बहुत बढ़ी नहीं है, इन्हें हर विद्यार्थी के लिए समान शुल्क लागू करके रहत आसानी से दी जा सकती है।

अनुकूलता का सिद्धांत जानते हैं न, एक वर्ग ने अपने लिए संघर्ष जताए अपने प्रयास बढ़ा लिए और कुछ न होते हुए भी वे आज आगे हैं, दूसरे वर्ग को बैसाखियाँ इतनी धमा दी कि वे अपने पैरों की ताकत ही खो बैठे। बैसाखियाँ उतनी ही दीजिए जितनी आवश्यक हैं, कहीं अपना परिश्रम चरित्र ही न भूल जाएं एक पूरा तबका।

अनंत बैकलॉग सीट, भारत का लगभग हर विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, और बाहर हवा बेरोजगार घूम रहा है, कैसी विडम्बना है। बैकलॉग की सीट अतक तक की

खाली पड़ी रहेगी, लेकिन उसपर कोई योग्य बेरोजगार को वह सीट नहीं दी जाएगी, जब आपको योग्य लोग मिल जाएं वह सीट खाली करवा लीजिए, लेकिन जब तक नहीं मिलते हैं उनपर प्रवेश खुला रख उन युवाओं को दीजिए जो पढ़ना चाहते हैं।

और अब बात बिलकुल अभी अभी की, UGC किसी के साथ भी (दलित, वंचित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, विकलांग महिला, अनारक्षित आरक्षित कोई भी वर्ग) भेद होने पर समान डंड की व्यवस्था हो, जांच पहले डंड बाद में और झूठी शिकायत पाने पर तीन गुना डंड की व्यवस्था, केवल यही तीन परिवर्तन चाहता है हर न्यायप्रिय मनुष्य चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग से आता हो।

यकीन मानिए हम सब भारतीय भारत को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, जहां सभी समृद्ध हों, सभी सुखी हों। समृद्धि किसे बुरी लागती है, दरिद्रता किसे भाती है, हम सब यह भी जानते हैं कि हम अकेले आगे बढ़ें तो यह अधूरी समृद्धि होगी, अधूरा विकास होगा। इसलिए समस्त विसंगतियों के बाद भी सामाजिक न्याय की अवधारणा, लोक हितकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) को अपनाया गया, उसी संविधान के अंतर्गत ही जड़ताओं पर प्रहार किया है अब कोई किसी से जाति पूछ कर साथ नहीं बैठता समाज में, कार्यस्थलों पर जाति पूछकर भोजन पानी नहीं लिया जाता, भंडारों में सब वैषण्य ही माने जाते हैं, मंदिरों में जाति नहीं पूछी जाती, अपवाद छोड़ दे कुछ कुस्तित मानसिकता वाले हर कहीं होते हैं, उनमें से भी अनेक क्षुद्र राजनीति से प्रेरित, अन्यायी भौतिक समृद्धि में जाति की दीवारों वैसे ही ढह जाती हैं, रोटी बेटी के संबंध बहुत सामान्य हो चले हैं, किंतु मंच से बेटों के लिए कहीं जाने वाली आपत्तिजनक बातें किसी भी समुदाय की बेटे बहन के लिए स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।

सब मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं, किंतु राष्ट्र प्रथम रहे, अपने भेद मिटाएं जाएं। यदि सत्ता भ्रमित हो रही हो तो जनमानस का यह कर्तव्य है कि वह उसे उसके कर्तव्य याद दिलाए, और कहे कि हमें बंटाने के हर प्रयास को हम असफल करे, कर रहे हैं।

हम भ्रमित न हो, आखिर में पीड़ित आम इंसान ही होता है, दुःख आम इंसान के हिस्से आते हैं, और पीड़ा और दुःख का भी न कोई जाति होती है न कोई धर्म।

आइये 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की अवधारणा पर काम करें, एक सामान्य मनुष्य के हथ में केवल यही है कि वह शुभ भावनाओं को प्रत्याभूत कर सके अपने अपने स्तर पर।

मात्र में हो निमहंस: उत्तर भारत की जरूरत व राष्ट्रीय प्राथमिकता



मानसिक सेहत

डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी

कंसल्टंट साइकियाट्रिस्ट

केन्द्र सरकार ने हाल ही में आम बजट में उत्तर भारत में निमहंस 2.0 (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडल हेल्थ एंड यूरो साइंस) स्थापित करने की घोषणा की है। केन्द्र सरकार ने यह घोषणा कर स्पष्ट संदेश दिया है कि वह मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील है और बढ़ते मानसिक रोगों के बोझ को कम करने के लिए गंभीरता से काम करना चाहती है। यह निर्णय सराहनीय है क्योंकि सरकार अब मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे की अग्रिम पंक्ति में रख रही है।

देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जारी एक नयी रिपोर्ट ने बीते दिनों हड़कंप मचा दिया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर पांचवां किशोर या युवा, किसी न किसी स्तर के डिप्रेशन, एंजायटी या अन्य मानसिक विकार से जूझ रहा है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसायटी की 77 वीं वार्षिक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एनिसिस 2026 में यह तथ्य चिंता का विषय था कि भारत में करीब 60 प्रतिशत मानसिक रोग 35 साल से कम उम्र के लोगों में पाए जा रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने, करियर बनाने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने की उम्र में मानसिक समस्याओं के शुरू हो जाने से इनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अध्ययनों और अनुभवों ने यह तथ्य भी रखा है कि कोविड-19 महामारी, आर्थिक अस्थिरता और बदलती सामाजिक संरचना ने युवाओं के तनाव को और बढ़ा दिया है।

जब 60 प्रतिशत मानसिक रोग 35 साल से कम उम्र में ही सामने आ रहे हैं, तो यह समस्या अधिक ध्यान आकृष्ट करती है। एक तरह से यह

देख की मानसिक सेहत का नक्शा भी है। भारत में मानसिक रोगों के बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि लोग समय पर इलाज के बारे में जागरूक नहीं हैं। अगर मानसिक समस्याओं की पहचान शुरुआती दौर में हो जाए, तो लगभग सभी मानसिक रोगों का सफल इलाज संभव है और व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है।

इन तथ्यों के साथ यह भी स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में स्थित प्रतिष्ठित निमहंस पहले से ही पूरे देश के मरीजों का अत्यधिक भर संपाल रही है। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के मरीजों को इलाज के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में बजट में घोषित निमहंस 2.0 का संदेश उज्युक स्थान मध्यप्रदेश है क्योंकि यह देश के भौगोलिक केंद्र में है और उत्तर भारत के विशाल जनसमूह के लिए स्वाभाविक रूप से सुलभ है।

मध्यप्रदेश में इस संस्थान की स्थापना से उत्तरप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली-पुणेसीआर, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड तक के लाखों लोगों को तृतीयक स्तर की मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सहजता से मिल सकेंगी। आज डिप्रेशन, एंजायटी, सवर्टिस यूज, डिजिटल एडिशन और न्यूरोलॉजिकल विकारों का बोझ तेजी से बढ़ रहा है, जबकि सुपर-स्पेशियलिटी संस्थान बहुत कम हैं। निमहंस 2.0 इस कमी को पूरा करते हुए रिस्क, ट्रेनिंग और नीति-निर्माण का राष्ट्रीय केंद्र बनेगा।

इस आलेख के माध्यम से मैं आमजन, मनोचिकित्सकों, न्यूरोलॉजिस्टों और न्यूरो सर्जनों से अपील करता हूँ कि उत्तर भारत में निमहंस 2.0 को मध्यप्रदेश में स्थापित कराने के लिए अपना-अपना योगदान दें। यह सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि अपना वाले वहाँ की मानसिक स्वास्थ्य क्रांति की नींव है। सरकार का यह दूरदर्शी कदम तभी सफल होगा जब समाज और विशेषज्ञ मिलकर इसे आगे बढ़ाएँ।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-वी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जेन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विवाद लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

तन-बदन में आग लगते शब्द याने कि शब्दास्त्र



तंत्र

राजेंद्र बाज

लेखक व्यंग्यकार हैं।

इसमें कोई दो मत नहीं कि शब्दों का अस्त्र याने कि 'शब्दास्त्र' का असर भी ब्रह्मास्त्र के समकक्ष हो सकता है। कोई जरूरत नहीं है वाद-विवाद अथवा टकराव की स्थिति में अस्त्र-शस्त्र उठाने की, आप मजे में 32 दांतों के बीच मचलती जुबान चलाकर भी मनोरथ की प्राप्ति कर सकते हैं। सही समय पर सही शब्द का उपयोग भी एक कला है। कभी-कभी तो एक ही चुनिंदा शब्द विशेषी पक्ष के तन-बदन में आग लगा देता है। अब यदि हमें लेकर विरोधी पक्ष द्वारा उछले गए घातक और मारक शब्द की काट नहीं की जाए तो निश्चित रूप से अवसाद में डूब जाने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता ही शेष

नहीं बचता।

इसलिए विशेष कर राजनीति के मैदान में उठे रहने के लिए हर छोटे-बड़े राजनेता को शब्दकोश खंगाल कर चुनिंदा शब्दों का संग्रह तैयार कर लेना चाहिए। इसके चलते राजनीति में चाहे सम परिस्थिति हो या विषम, हर एक स्थिति में आत्मविश्वास ही इस कदर प्रबल हो जाता है कि चोरी करने पर भी सीनाजोरी करने लायक पर्याप्त सामर्थ्य आ जाता है। आध्यात्मिक एवं भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी शब्दों की महिमा को अपरंपर दर्शाया गया है। इसलिए यदि हमारे पास कुछ भी नहीं हो लेकिन दिल और दिमाग में शब्दों का भंडार हो तो केवल राजनीति ही नहीं अपितु व्यापार व्यवसाय या किसी पेशे में भी अपना डंका बजाया जा सकता है। खैर।

लोकतंत्र के चलते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दौर में तो यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि शब्दों के हथियार



साथ रखे जाएं। अन्यथा राजनीति के मैदान

में राह चलते हर कोई राह चलता हमें धराशाही कर सकता है। वैसे आए दिन राजनेताओं की जुबान इस कदर फिसल भी जाती है कि कुर्सी पर बैठे हुए हो तो कुर्सी फिसल जाने का अंदेश हो जाता है। या

फिर कुर्सी पाने की अभिलाषा तार-तार हो जाती है। इसलिए यह भी जरूरी है कि कुछ एक मामलों में मन की भड़ास को चुमावदार शब्दों का उपयोग करते हुए व्यक्त कर दी जाएं। लेकिन इस कला में पारंगत होने के लिए भी राजनेताओं को शब्द ज्ञानी बनाने की जरूरत है।

आजकल के दौर में कब सेर को सवा सेर मिल जाएं? यह कबसे तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि राजनीति में अपने मूल उद्देश्य (?) को पाने के लिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से तमाम

तरह के संसदीय एवं असंसदीय शब्दों का दिल और दिमाग में संचय कर लिया जाए। इसका सीधा लाभ यह होगा कि जब हमें कोई सवा सेर मिल जाएं तो हम डेढ़ सेर सिद्ध हो सकेंगे और इसी अनुपात में अपने

शब्दिक सामर्थ्य के बलबूते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रसास्वादन कर सकें। व्यवहार में देखा गया है कि शब्दों से खेल-मामलों में मन की भड़ास को सिंहासन पर भी विराजमान होती रही है।

जनमानस को ल

डेटा के जंगल में खोती मानवीय संवेदना

डिजिटल संस्कृति पर काम करने वाली मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री शोरी टर्कल ने अपनी शोध में बार-बार चेताया है कि तकनीक हमें 'जुड़े हुए लेकिन अकेले' बना रही है। उनका तर्क है कि डिजिटल इंटरफेस भावनात्मक जटिलताओं को सरल संकेतों में बदल देता है जैसे इमोजी, लाइक और कमेंट में। यह बदलाव केवल सुविधा का नहीं, संवेदना के क्षरण का संकेत है। गहन पठन वह प्रक्रिया है जिसमें पाठक पात्रों के साथ दुखी होता है, उनके संघर्ष में खुद को देखता है और समाज को नए नज़रिए से समझता है।



दृष्टिकोण

डॉ. मनीष जैसल

मीडिया प्राध्यापक और टिप्पणीकार

आज मानव सभ्यता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ स्मृति, संस्कृति और अनुभव, तीनों तेज़ी से डेटा में बदल रहे हैं। जो इतिहास कभी मौखिक परंपराओं में बहता था, जो साहित्य पाठक के भीतर भावनात्मक कंपन पैदा करता था, और जो सामाजिक जीवन रितियों की गर्माहट से चलता था, वह अब एल्गोरिथ्म, सर्वर और डिजिटल आर्काइव्स में संरक्षित हो रहा है। डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ इसी परिवर्तन का एक अकादमिक नाम है। इसका उद्देश्य ज्ञान को सुरक्षित करना, सुलभ बनाना और नए तरीकों से विश्लेषित जानकार मानते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह भी है कि इस प्रक्रिया में मानवीय संवेदना धीरे-धीरे ऑकड़ों की भीड़ में दबती जा रही है।

मीडिया सिद्धांतकार मार्शल मैकलुहान ने दशकों पहले कहा था कि हर नई तकनीक केवल सूचना का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह मनुष्य की सोचने और महसूस करने की संरचना को बदल देती है। उनका प्रसिद्ध विचार था कि 'माध्यम ही संदेश है।' आज डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ इसी सिद्धांत को साकार करती दिखती है, जहाँ किताब का अर्थ बदल रहा है क्योंकि उसका माध्यम बदल चुका है।

आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पुस्तक परियोजना गूगल बुक्स है। कंपनी के सार्वजनिक ऑकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 4 करोड़ से अधिक किताबें स्कैन की जा चुकी हैं। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की दुर्लभ रचनाएँ अब ऑनलाइन खोजी जा सकती हैं। लेकिन इसी परियोजना पर कई शोध यह भी दिखाते हैं कि पाठकों का व्यवहार बदल गया है। अधिकारिता उपयोगकर्ता किताबें पूरी पढ़ने के बजाय शब्द खोजते हैं, अंश उठाते हैं और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं।

डिजिटल संस्कृति पर काम करने वाली मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री शोरी टर्कल ने अपनी शोध में बार-बार चेताया है कि तकनीक हमें 'जुड़े हुए लेकिन अकेले' बना रही है। उनका तर्क है कि डिजिटल इंटरफेस भावनात्मक जटिलताओं को सरल संकेतों में बदल देता है जैसे इमोजी, लाइक और कमेंट में। यह

बदलाव केवल सुविधा का नहीं, संवेदना के क्षरण का संकेत है। गहन पठन वह प्रक्रिया है जिसमें पाठक पात्रों के साथ दुखी होता है, उनके संघर्ष में खुद को देखता है और समाज को नए नज़रिए से समझता है।

इतिहास के क्षेत्र में यह संकट और गहरा है। विश्वभर में संग्रहालय और आर्काइव्स अपने डिजिटल रूप दे रहे हैं ताकि समय और आपदाओं से उन्हें बचाया जा सके। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की लगभग 60 प्रतिशत सांस्कृतिक धरोहर नष्ट होने के खतरे में है, इसलिए डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन इसी संस्था की रिपोर्ट यह भी बताती है कि डिजिटल हो रही सामग्री में भारी हिस्सा औपनिवेशिक और संस्थागत रिकॉर्ड का है। यानी सत्ता के पास जो इतिहास था, वही डिजिटल भविष्य में भी हावी हो रहा है।

भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों की मौखिक परंपराएँ, लोककथाएँ और स्मृति-आधारित इतिहास डिजिटल डेटाबेस में बहुत कम दिखाई देते हैं। कारण साफ़ है, एल्गोरिथ्म लिखित, संरचित और स्कैन योग्य सामग्री को प्राथमिकता देता है। परिणाम यह होता है कि डिजिटल इतिहास देखने में विशाल लगता है, लेकिन उसमें आम लोगों की आवाज़ें गायब रहती हैं।

इस क्षेत्र के प्रमुख विद्वान Franco Moretti ने 'डिस्टेंट रीडिंग' की अवधारणा पेश की, जिसमें हजारों पुस्तकों को एक साथ डेटा के रूप में विश्लेषित किया जाता है, बजाय कुछ रचनाओं को गहराई से पढ़ने के। मोरेती ने इसे साहित्य को समझने का नया तरीका

बताया, लेकिन कई आलोचकों ने इसे साहित्यिक संवेदना से कटाव का माध्यम माना। स्वयं मोरेती ने स्वीकार किया कि इस पद्धति में व्यक्तिगत अनुभव और भावनात्मक गहराई पीछे छूट जाती है।

कई अकादमिक अध्ययनों ने दिखाया है कि इस गूगल बुक्स संग्रह में अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाओं की

मिलियन ट्वीट्स किसान आंदोलन से जुड़े हुए दर्ज किए गए। नेटवर्क एनालिसिस, सेंटिमेंट स्टडी और ट्रेड मैपिंग पर आधारित कई डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ शोध हुए। डेटा से यह साबित हुआ कि आंदोलन वैश्विक स्तर पर चर्चा में था। लेकिन यही डेटा यह नहीं दिखा सका कि महीनों सड़कों पर बैठे किसानों पर मानसिक तनाव कितना भारी था, कितने परिवार आर्थिक संकट में गए और कितनों ने अपनों को खोया। डिजिटल विश्लेषण ने आंदोलन का आकार दिखाया, उसकी पीड़ा नहीं।

ओईसीडी की 2022 की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जो छात्र अत्यधिक डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं, उनमें आलोचनात्मक सोच और गहन विश्लेषण क्षमता अपेक्षाकृत कम पाई गई। स्क्रीन पर तेज़ी से स्क्रॉल करने की आदत वन्यूल प्रतिकृति मौजूद रहे। यह तकनीकी उपलब्धि है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक थ्री-डी मॉडल उस सांस्कृतिक स्मृति की भरपाई कर सकता है, जो पीढ़ियों से उन स्थलों से जुड़ी थी? मंदिर, मस्जिद या बाजार केवल संरचना नहीं होते, वे सामाजिक जीवन के केंद्र होते हैं।

डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ को यह स्वीकार करना होगा कि हर इतिहास स्कैन नहीं हो सकता, हर भावना ग्राफ़ में नहीं उतर सकती और हर संस्कृति एल्गोरिथ्म की भाषा नहीं बोलती। डेटा का जंगल हर दिन घना होता जा रहा है। खतरा रोशनी भी है, रास्ते भी हैं, लेकिन भटकने का उल्टा भी उतना ही बड़ा है। अगर हम केवल ऑकड़ों पर भरोसा करेंगे और मानवीय संवेदना को पीछे छोड़ देंगे, तो हमारे पास सूचना का अंबार होगा, लेकिन समझ का अकाल।

डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ का मूल संकट यही है कि वह



विवार

चैतन्य नागर

लेखक पत्रकार हैं।

धीरे-धीरे देह की सीढ़ियाँ चढ़ती है उम्र। आहिस्ता-आहिस्ता दीर्घक समय कुरुरता है हड्डियों को। लवचा सिकुड़ती है वगैर किसी शोर-शराबे के। आँखों की रोशनी बुझने लगती है। ऐसा नहीं होता कि अचानक कोई सुबह उठे और देखे कि वह बुढ़ा हो गया है। ऐसी ही है जीवन की सांझ-इसकी आहट किसी कैलेंडर की तारीख से नहीं, बल्कि आईने से झाँकते उस खामोश सच से आती है जिसमें हमें अक्सर जेरंटॉफोबिया या बुढ़ापे का डर दिखाई देता है। यह डर वक्त के बीतने का नहीं, जितना कि अपने वजूद के धीरे-धीरे घुलने का है। घबराहट होती है कि व्यक्तिगत पहचान की जिस इमारत को हमने ताकत, सौन्दर्य और उपयोगिता की चट्टान पर बनाया था, वह कहीं भविष्य की धुंधली अनिश्चितता में ढह न जाए।

इस डर की गहराई को समझने के लिए उस ढाँचे को देखना चाहिए जो हमने अपने अहंकार की नींव पर बनाया है। दुनिया हमें सिखाती है कि हमारे होने का अर्थ है लगातार कुछ करते रहना, कुछ न कुछ बनाते-बनाते जाना और लोगों को प्रभावित भी करना। जब देह के पछिये घिसने लगते हैं, तो मन में एक अजीब तरह का शोक उतरने लगता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक बुढ़ापे की चिंता अक्सर अपनी स्वायत्तता को खोने से जुड़ी होती है। बचपन में होने वाले भय का एक दिलचस्प और दर्दनाक विलोम है यहा एक बच्चा अंधेरे में खो जाने से डरता है; बुजुर्ग समाज की भीड़ में ओझल हो जाने से। वह अपनों पर ही बोझ बन जाने से डरता है। जिस दुनिया में सिर्फ नवीन, शक्तिशाली और गतिमान को पूजा जाता है, वहाँ पुराना अक्सर हाशिए पर

पुरानी वीणाओं पर भी बजती हैं सुरीली धुनें

दुनिया हमें सिखाती है कि हमारे होने का अर्थ है लगातार कुछ करते रहना, कुछ न कुछ बनाते-बनाते जाना और लोगों को प्रभावित भी करना। जब देह के पहिये घिसने लगते हैं, तो मन में एक अजीब तरह का शोक उतरने लगता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक बुढ़ापे की चिंता अक्सर अपनी स्वायत्तता को खोने से जुड़ी होती है। बचपन में होने वाले भय का एक दिलचस्प और दर्दनाक विलोम है यहा एक बच्चा अंधेरे में खो जाने से डरता है; बुजुर्ग समाज की भीड़ में ओझल हो जाने से। वह अपनों पर ही बोझ बन जाने से डरता है। जिस दुनिया में सिर्फ नवीन, शक्तिशाली और गतिमान को पूजा जाता है, वहाँ पुराना अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। उम्र का लिहाज पहले हमारी संस्कृति का हिस्सा था, वृद्ध लोगों की इज्जत करना बचपन से ही सिखाया जाता था। अब ऐसा नहीं रहा। पश्चिम की संस्कृतियाँ यौवन की तारीफ करते नहीं थकतीं वृद्ध वहाँ अनुपयोगी हो जाता है। अर्थव्यवस्था पर एक बोझ और किसी काम के लिए अनुपयुक्त। अक्सर हम झुर्रियों से सिर्फ झमेलिए नहीं डरते कि वे खराब दिखती हैं, बल्कि इसलिए कि वे समाज के लिए हमारी अनुपयोगिता का प्रतीक बन जाती हैं।

साहित्य ने हमारे इस डर बखूबी बयान किया है। ऑस्कर वाइल्ड के कालजयी उपन्यास 'द पिक्चर ऑफ़ डोरियन ग्रे' को याद करें। डोरियन का डर मौत से ज्यादा बदलाव को लेकर है। वह जानता है कि उसकी ताकत और आकर्षण उसकी शोशे जैसी चिकनी लवचा में है। उसका लगातार बुढ़ा और बदसूरत होता चित्र इसी बात का प्रतीक है कि हम अपने भीतर के डर को चाहे कितना भी छिपा लें, समय की सुझाया किसी के लिए नहीं रुकतीं। शेक्सपियर के 'किंग लियर' की त्रासदी सिर्फ सत्ता को नहीं, बल्कि उस गरिमा को खोने में है जो उसे समाज में प्रासंगिक बनाए रखती थी। इसकी चीख दरअसल संज्ञानात्मक पतन और स्मृति के धुंधलाने का वह सार्वभौमिक डर है, जो हर इंसान को

सताता है। अज्ञेय की कविताओं में बुढ़ापे अक्सर एक खाली घर की तरह आता है। वे लिखते हैं कि उम्र के साथ शब्द साथ छोड़ देते हैं और मनुष्य अपनी ही स्मृतियों के पिंजरे में कैद हो जाता है। कँवर नारायण बुढ़ापे को एक ऐसी 'किताब' की तरह देखते हैं जिसे अब कोई पढ़ना नहीं चाहता। मुक्तिबोध की कविताओं में बुढ़ापे एक अंधेरे की तरह आता और यह समझौते का पर्याय है, जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं। मंगलेश डब्राल की कविताओं में यह डर 'घर खो जाने' के डर जैसा है।

जहाँ साहित्य हमारे जख्मों को दिखाता है, वहीं धर्मग्रंथ उन पर मरहम लगाते हैं। कई बार वे ढलते शरीर को एक 'दुर्लभ मकान' के रूप में नहीं, बल्कि एक परिपक्व होती 'आत्मा' के रूप में देखते हैं। बाइबिल के 'एक्लेसिएस्टस' में बुढ़ापे का वर्णन बहुत ही बेबाक और सच्चा है। वहाँ शरीर को एक ऐसे घर की तरह बताया गया है जिसके खिड़कियाँ धुंधली हो गई हैं और पहरेदार कांप रहे हैं। लेकिन, इसे दुख की तरह नहीं बल्कि एक 'पवित्र उल्टी गिनती' की तरह पेश किया गया है। ऐसे भी विचार हैं जो हमें शरीर के साथ होने वाले जुड़ाव से शायद मुक्त करते हैं। वृद्ध का दिखना राजकुमार सिद्धार्थ के लिए वैराग्य और नवीन अंतर्दृष्टि का कारण बना। बुढ़ापे उनके लिए

'अनित्यता' या अनिष्क का सन्देश लेकर आता है।

आज का मनोवैज्ञान बुढ़ापे के बारे में एक सकारात्मक कहानी भी सुनाता है। जिसे हम 'कमी' समझते हैं, वह अक्सर एक बहुत बड़ी 'उपलब्धि' होती है। जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, लोग उन रिसर्शों को छोड़ देते हैं जो केवल औपचारिक या दिखावे मात्र के होते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा केवल उन लोगों पर खर्च करते हैं जिनसे उन्हें सच्चा प्रेम मिलता है। बुढ़ापे में भले ही सीखने की गति कम हो जाए, लेकिन जीवन भर का संचित अनुभव एक ऐसी बुद्धिमत्ता को जन्म देता है, जो युवाओं के पास नहीं होती। यह समस्याओं को सुलझाने की वह जादुई क्षमता है जो केवल वक्त के साथ आती है। समाजशास्त्री लार्स टॉर्नस्ट्रॉम के अनुसार, बुढ़ापे में व्यक्ति भौतिकवादी दुनिया से ऊपर उठकर एक ब्रह्मांडीय नजरिया अपना लेता है। वह अब खुद को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानने लगता है।

देखा जाए तो, बुढ़ापे सिर्फ बंद होते दरवाजों और खिड़कियों का नाम नहीं, बल्कि एक नए नजरिए के खुलने का भी संकेत है। यह वह समय है जब हम नायक बनने की होड़ को एक तरफ सरका कर जीवन के द्रष्टा बन जाते हैं। अथर्ववेद की प्रार्थना 'पश्येम शरतः शतम्' (हम सौ

शरद ऋतुएं देखें) हमें सिखाती है कि लंबी उम्र एक सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है। अगर जीवन एक उपन्यास जैसा है, तो बुढ़ापे उसका अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि उसका सार है—वह क्षण जहाँ कहानी के सभी बिखरे हुए तार एक सुंदर पैटर्न में जुड़ जाते हैं। बालों का सफेद होना सिर्फ रोशनी का कम होना नहीं, बल्कि आत्मा का स्वच्छ होना भी है।

बुढ़ापे नए उर लाता है और नए अवसर भी। यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम चुनते क्या है। बुढ़ापे इस बात का सबूत है कि हमने दिन की तपिश को झेला है ताकि सांझ की शीतलता तक पहुँच सकें। भागदौड़ से निकलकर अब हम लहरों की उस लय में भी शामिल हो जाते हैं, जहाँ शांति ही संगीत है। झुर्रियों से भरी देह और क्लांत मन के पास भी शायद इस चयन की ऊर्जा तो बचती ही है। ऊँचे पहाड़ों पर चढ़ जाएँ तो साँसों तो फूलती हैं, पर पर्वतों का सौन्दर्य अपनी पूरी गरिमा के साथ दिखाई भी देता है। अंग्रेजी कवि एमरिस कहता था कि सबसे बेहदरीन धुनें उन्हीं वायलिन पर बजती हैं जो सबसे पुरानी होती हैं। संगीतकार भले ही इस बात पर बहस करें, पर बुढ़ापे की गरिमा को कायम रखने के लिए तो यह ख्याल तो बढ़िया है!



विक्रमोत्सव 2026

डॉ. हरीशकुमार सिंह

महाभारत और रामायण के युद्ध में प्रमुख अंतर युग, उद्देश्य और युद्ध की प्रकृति का रहा है। रामायण त्रेता युग में आज से लगभग नौ लाख वर्ष पूर्व घटित हुई जबकि महाभारत द्वापरयुग में लगभग आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व हुआ। रामायण का युद्ध भगवान राम और पंडित रावण के बीच सीमित था तो महाभारत में देश के सभी राज्य सम्मिलित थे और यह विश्वयुद्ध ही था। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम मर्यादा, त्याग और रिसर्तों को महत्व देते हैं तो महाभारत में श्रीकृष्ण कूटनीति, अधिकार और ज्ञान को प्रमुखता देते हैं। महाभारत में कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव आमने सामने हैं और दोनों के पक्ष में अपने अपने विश्वसनीय राज्यों के राजा और उनकी सेना हैं। अठारह दिन चले महाभारत के युद्ध में दोनों और कई महारथी हैं जिनसे हम सभी परिचित हैं। मगर इन महारथियों के शस्त्र और अस्त्र महारथियों के नाम की तरह ही अनुपम, अनूठे, अलौकिक और विज्ञान सम्मत हैं और कइयों ने ये शस्त्र और अस्त्र अपने गुरुओं की सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर या तपस्या कर महर्षि परशुराम, देवताओं के राजा इंद्र और सूर्यदेव आदि से प्राप्त किये थे। ऐसे ही शस्त्र और अस्त्र से परिचित कराती हैं उज्जयिनी में चल रहे विक्रमोत्सव के अंतर्गत, विक्रमादित्य शोभा पीठ में लगी विशाल और भव्य प्रदर्शनी-द्वय महाभारत। महाभारत प्रदर्शनी में महाभारत के युद्ध में दोनों और के सेनापतियों द्वारा ग्यारह विभिन्न जटिल व्यूह रचनाओं का उपयोग किया गया था और इन व्यूह

उन्नत तकनीक और आध्यात्म से परिपूर्ण महाभारत के अस्त्र-शस्त्र

रचनाओं को प्रतीकात्मकता से बहुत सुन्दरता से प्रदर्शित किया गया है। कौरवों की और से गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे कठिन व्यूह रचना चक्रव्यूह निर्मित की थी जिसमें अन्दर जाने का रास्ता तो था मगर बाहर निकलने का नहीं और यह अर्जुन की अनुपस्थिति में उनके पुत्र, अभिमन्यु को फंसाने के लिए थी और युद्ध के दिन अभिमन्यु इसमें फंसेकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। चक्रव्यूह से हम सभी भलीभाँति परिचित हैं मगर युद्ध के अठारह दिनों में भीष्म ने गरुड़ व्यूह, मंडल व्यूह और मकर व्यूह, अर्जुन द्वारा वज्र एवं अर्धचन्द्र व्यूह, पांडवों का क्रॉच व्यूह, गुरु द्रोण द्वारा चक्रशकट व्यूह, कच्छप व्यूह, श्रीनातका व्यूह, ओरमी व्यूह, सर्वतोमुखी दंड व्यूह का प्रदर्शन हुबहू किया है क्योंकि ये व्यूह शत्रु की रणनीति को असफल करने के लिए निर्मित किये जाते थे और यह बताते हैं कि महाभारत काल में सेनापतियों का विवेक और चिंतन अत्यंत उन्नत और वैज्ञानिक था। उदहारण के लिए गरुड़ व्यूह, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के अनुरूप था जिसमें सेना का अग्रभाग तेज, सुदृढ़ पार्श्व और विस्तृत पृष्ठभाग। गरुड़ व्यूह वेग, प्रतीक और आक्रामक सैन्य कला का प्रतीक है और इन व्यूहों का आधार ज्यामिति भी है। प्रदर्शनी महाभारत में इन



व्यूहों की रचना देखना रोमांचित करता है।

इस प्रदर्शनी में अर्जुन का प्रख्यात धनुष गांडीव (जिसे अर्जुन को अंगिदेव द्वारा प्रदान किया गया था), नकुल-सहदेव का आग्नेय धनुष, कर्ण का विजय धनुष, दुर्योधन का शरामन धनुष, युधिष्ठिर का रौद्र धनुष और वैजयंती धनुष, भीष्म का अजगव धनुष, अश्वत्थामा का कोदण्ड धनुष, घटोत्कच का पौलस्त्य धनुष, शिव जी का पिनाक धनुष, सुतसोम का आग्नेय धनुष, अर्जुन का अक्षय तुषणी (कभी न समाप्त होने वाले बाणों का दिव्या तरकरा) आदि

प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किये गये हैं। भगवान श्रीकृष्ण का धर्म और न्याय का प्रतीक सुदर्शन चक्र भी दिव्यता के साथ यहाँ मौजूद है। भीम और दुर्योधन की गदाएँ, फरसे, तलवार, भाले और वज्र भी प्रदर्शनी में हैं और ऐसे करीब सौ से अधिक अस्त्र- शस्त्र यहाँ हैं। महाभारत में एक और अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। ब्रह्मास्त्र के अलावा ब्रह्माद्वास्त्र, ब्रह्मिशास्त्र, अन्जलिकास्त्र, नारायणास्त्र आदि भी दर्शाए गये हैं। चतुरंगिनी सेना के बारे में भी चित्रित और प्रदर्शित किया गया है।

असल में जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें सामने वाले को किसी भी तरह मारना-काटना ही युद्ध का प्रमुख उद्देश्य रहा है मगर महाभारत का महायुद्ध सिर्फ दो सेनाओं का भीषण युद्ध नहीं बल्कि उस समय की उन्नत प्रौद्योगिकी, ऋषियों के ज्ञान और योद्धाओं को शस्त्र का वरदान देना, अस्त्र और शस्त्र का मन्त्र की शक्तियों से चलना, महारथियों की विज्ञानपरक समझ से उपजे अस्त्र और शस्त्र का उपयोग था जिसमें रणनीतिक कौशल के लिए शास्त्र सम्मत व्यूह रचना के कारण महाभारत सबको आकर्षित करता है। पांडवों की और से भगवान श्रीकृष्ण ने बिना शस्त्र उठये, अपने ज्ञान और कूटनीति से पांडवों को विजयी दिलाई। महाभारत के अस्त्र, शस्त्र, शौर्य और विज्ञान का दिव्य संगम है यह प्रदर्शनी महाभारत। अस्त्र और शस्त्र के साथ उनकी महत्ता को प्रदर्शित करते आलेख दर्शकों को सहूलियत प्रदान करते हैं। प्रदर्शनी में पोस्टरों के जरिये महाभारत के अठारह दिन के युद्ध का वर्णन पढ़ना रोमांचित करता है। प्रदर्शनी के शोधकर्ता और क्यूरेटर राज बेंद्रे बताते हैं कि महाभारत शौर्य, विज्ञान और आध्यात्म का संगम था और महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं, सभ्यता का आईना भी है। राज बेंद्रे के अनुसार इस प्रदर्शनी के लिए काफी अनुसन्धान किया गया है और प्रदर्शनी का उद्देश्य महाभारत को पौराणिक ग्रन्थ के साथ भारत की प्राचीन सैन्य, वैज्ञानिक, और रणनीतिक चेतना का दर्शावेज भी सिद्ध करना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मदन मोहन मालवी की परिकल्पना है विक्रमोत्सव और उनके सांस्कृतिक सलाहकार डॉ. श्रीराम तिवारी के संयोजन में महाभारत प्रदर्शनी अनूठी और अनुपम ज्ञान का सागर है।

जनसुनवाई

जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई में 100 आवेदनों को निर्धारित समयावधि में निराकरण के निर्देश

सोहामपुर। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई अवर कलेक्टर अनिल जैन की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस अवसर पर नागरिकों ने करीबन 100 आवेदन श्रम, वित्त, राजस्व, अनुकंपा नियुक्ति आदि समस्याओं के लिए सुनवाई के दौरान प्रदान किए थे। अवर कलेक्टर श्री जैन ने प्राप्त आवेदनों पर विचार करते संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। आवेदनों में नागरिकों की समस्याओं का परीक्षण करके विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदनों



का समाधान किया गया। जनसुनवाई में पहुंचे ग्राम-दहलवाड़ा तहसील-बनछेड़ी निवासी शिवम राय ने उनके पिता के स्थान पर ग्राम पंचायत सचिव के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का आवेदन प्रदान किया था। श्री जैन ने संबंधित अधिकारी को उक्त समस्या के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं डोलारिया निवासी रवि प्रसाद बनवारी ने आवास योजना का लाभ प्रदान करने का आवेदन दिया था। श्री जैन ने मुख्य कार्यालय अधिकारी जनपद डोलारिया को उचित सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। इसी क्रम में कृषि-भूमि सीमांकन, अतिक्रमण की समस्या, नजूल रिकॉर्ड अद्यतन, पट्टा वितरण, अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया। इस अवसर पर अवर कलेक्टर बुजेंद्र रावत, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती डॉ. बबिता राठी, डिप्टी कलेक्टर नीता कोरी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

प्रिंट और डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों को ब्रह्माकुमारीज़ ने किया सम्मानित

प्रोफेसर गिरीश ने सार्थक संवाद के माध्यम से बताए नकारात्मक वातावरण में भी सकारात्मक रहने के तरीके

बैतूल। ब्रह्माकुमारी संस्थान के स्थानीय सेवाकेंद्र भाग्यविधाता भवन बटापामा में आज बधवार को सुबह 10.30 बजे से पत्रकार बंधुओं, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए 'विशेष संवाद एवं सम्मान समारोह' का आयोजन आध्यात्मिक एवं दिव्य वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, कॉरपोरेट ट्रेनर एवं लाइफ कोच मुंबई से पधार प्रोफेसर ई. वी. गिरीश ने अपने प्रेरक उद्बोधन में पत्रकारिता को समाज का सजग दर्पण बताते हुए सभी को उनके प्रयासों, कार्यों और देश व समाज के प्रति योगदान को सराहा। उन्होंने सभी को आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ समझाते हुए कहा कि आध्यात्मिकता का मतलब धर्म, जाति, लिंग, आयु की सीमाओं से ऊपर उठकर सबको एक जैसी दृष्टि और समान भाव से देखना और इसे व्यवहार में लाना है। हमें स्वयं को, परिवार और समाज के लिए अच्छा बनना है। आज के बदलते और तनावपूर्ण माहौल में स्वयं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपका मन, आत्मा सशक्त रहेगी तो आप बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना भी अच्छे से कर सकोगे। उन्होंने उपस्थित जनों से आह्वान किया कि वे अपने मन को सकारात्मक दिशा में स्थिर रखते हुए जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाएं। इस अवसर पर बैतूल सेवाकेंद्र प्रभारी ब्रह्माकुमारी मंजू दीदी ने सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए धन्यवाद व्यक्त करते हुए जानकारी दी कि आगामी 27, 28 फरवरी एवं 01 मार्च को तीन दिवसीय विशेष कार्यक्रम 'वाह जिंदगी वाह' का आयोजन किया जाएगा। जो प्रतिदिन सायं 6 से 8 बजे तक ब्रह्माकुमारीज़ भाग्यविधाता भवन बैतूल में आयोजित होगा। उन्होंने सभी से कार्यक्रम में सहभागिता का आग्रह किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करते हुए



उपस्थित सभी पत्रकारों को तिलक लगाकर सम्मान स्वरूप पटका पहनाकर अभिनंदन किया गया। वहीं इस सम्मान समारोह में पत्रकारिता में पीछेछड़ी करने वाले जिले के पहले पत्रकार डॉ. मयंक भागवत को प्रोफेसर ईवी गिरीश एवं भाग्य विधाता भवन की

प्रभारी मंजू दीदी द्वारा शाल-श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकार बंधुओं को गिफ्ट दिए गए और ब्रह्माकुमारी का आयोजन हुआ, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं ने आदर प्रेम के साथ स्वीकार किया।

मुंबई से आए प्रोफेसर ने सिखाए जिंदगी को खुशहाल बनाने के तरीके

ब्रह्माकुमारी संस्थान के भौरा सेवा केंद्र द्वारा मंगल भवन पंचायत परिसर भौरा में वाह जिंदगी वाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुंबई से पधार प्रोफेसर ईवी गिरीश ने अपने उद्बोधन में सभी को समाज का सजग दर्पण बताते हुए उनके परिवार तथा समाज के लिए किए प्रयासों, कार्यों और देश तथा समाज प्रति योगदान को सराहा। उन्होंने आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ समझाते हुए कहा कि आध्यात्मिकता धर्म, जाति, लिंग आयु की सीमाओं से ऊपर सबको एक जैसी दृष्टि और समान भाव से देखना और व्यवहार में आना है। यह स्वयं, परिवार और समाज के लिए अच्छा बनना है। आज के बदलते और तनावपूर्ण माहौल में स्वयं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित जनों से आह्वान किया कि वे अपने मन को सकारात्मक दिशा में स्थिर रखते हुए जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाएं। इस अवसर पर बैतूल सेवाकेंद्र प्रभारी ब्रह्माकुमारी मंजू दीदीजी ने सभी को जानकारी दी कि आगामी 27, 28 फरवरी एवं

1 मार्च को तीन दिवसीय विशेष कार्यक्रम वाह जिंदगी वाह का आयोजन किया गया है। जो प्रतिदिन सायं 6 बजे से 8 बजे तक ब्रह्माकुमारीज़ भाग्यविधाता भवन में आयोजित होगा। उन्होंने सभी से कार्यक्रम में सहभागिता का आग्रह किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करते हुए उपस्थित सभी लोगों को तिलक लगाकर सम्मान स्वरूप पटका पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारीज़ बैतूल की बीके मंजू दीदी, सारणी से बीके सुनीता दीदी, बीके अर्चना बहन, बीके सुनीता बहन, बीके नंदकिशोर भाई सहित भौरा के कई वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 820 गर्भवती महिलाओं की जांच, 349 हाई रिस्क मिली

बैतूल। गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं का पता लगाने और समय रहते उनका उपचार सुनिश्चित कर सुरक्षित प्रसव करवाने प्रतिमाह 9 एवं 25 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हरमांडे ने बताया कि 25 फरवरी को जिले में आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 820 गर्भवती महिलाओं की जांच एवं 349 हाई रिस्क चिन्हित तथा 75 महिलाओं की सोनोग्राफी की गई। शिविर में महिलाओं की खून की जांच एवं जीडीएम की जांच की गई। जिला चिकित्सालय बैतूल में आयोजित शिविर में स्त्री रोग चिकित्सक डॉ. भावना कवडकर द्वारा 58 गर्भवती महिलाओं की चिकित्सकीय जांच की गई, जिसमें 14 गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क के रूप में चिन्हित किया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. वंदना धाकड द्वारा 75 गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अम्बेडकर वार्ड शहरी क्षेत्र बैतूल में चिकित्सा अधिकारी डॉ कृष्णा मौसिक द्वारा 74 गर्भवती महिलाओं की चिकित्सकीय जांच की गई, जिसमें 31 गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क के रूप में



चिन्हित किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोडाडोंगरी में स्त्री रोग चिकित्सक डॉ कविता कोरी द्वारा 60 गर्भवती महिलाओं की जांच जिसमें 35 हाई रिस्क महिलाओं की जांच की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुलताई में स्त्री रोग चिकित्सक डॉ सरिता कालभोर द्वारा 73 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें 41 हाई रिस्क महिलाएं पाई गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेहरा में चिकित्सक अधिकारी डॉ अरविन सागरे द्वारा 96

गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें 26 महिलाएं हाई रिस्क पाई गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसदेही में चिकित्सा अधिकारी डॉ सरस्वती कंगाले परकाम द्वारा 46 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें 20 हाई रिस्क महिलाएं पाई गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर में चिकित्सा अधिकारी डॉ नीलम महजन द्वारा 65 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें 20 हाई रिस्क महिलाएं पाई गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभात पट्टन

आयु सीमा पूर्ण करने के कारण अपात्र हुई महिलाएं

जनवरी 2026 को 2899 लाइली बहना योजना से बाहर

एस द्विवेदी, बैतूल। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाइली बहना योजना का दायरा हर साल सिमटता जा रहा है। जब यह योजना शुरू हुई थी, तब इस योजना में हितग्राहियों की संख्या 2,81,527 दर्ज थी, लेकिन योजना शुरू होने से अब तक करीब 9 हजार लाइली बहने योजना से बाहर हो चुकी हैं। जो महिलाएं योजना से बाहर हुई हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है। बता दें कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के हित में लाइली बहना योजना शुरू की थी। वर्ष 2023 में लाइली बहना योजना में रजिस्ट्रेशन किए गए थे। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया गया, जिनके परिवार की आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। दूसरे चरण में उन महिलाओं को लाइली बहना योजना में जोड़ा गया, जिनके पति के नाम ट्रेक्टर था। जिले में वर्ष 2023 में 2 लाख 81 हजार 527 महिलाएं शामिल हुई थी। लेकिन अब इस योजना में 2 लाख 68 हजार 762 लाइली बहने हो रहे हैं। इस



योजना की मासिक राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। जिससे लाइली बहने को आर्थिक राहत की उम्मीद है।

तीन साल में 9078 महिलाएं योजना से बाहर - वर्तमान में योजना से जुड़ी कुल महिलाओं की संख्या 2 लाख 68 हजार 762 लाइली बहने बताई गई है, जबकि सत्यापित हितग्राहियों की संख्या 2,81,527 थी। इस दौरान महिलाओं कई महिलाओं की मृत्यु और अपनी स्वेच्छ से महिलाओं ने इस

योजना का परित्याग कर दिया। आधार से समग्र लिंक नहीं होने की वजह से भी महिलाएं अपात्र हो गईं। जबकि समग्र से नाम खिलित होने की वजह से महिलाओं का नाम सूची से हटया गया। वहीं जनवरी 2027 में 60 वर्ष की आयु पूरी करने से महिलाएं योजना से अपात्र हो गईं हैं। 2025 में 2993 महिलाएं और जनवरी 2024 में 3186 लाइली बहनाएं अपात्र हो गई थी। देखा जाए तो हर साल लाइली बहने की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है।

वंचित महिलाएं कर रही योजना शुरू होने का इंतजार

वंचित महिलाएं लाइली बहना योजना का पंजीयन पुनः शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। कई महिलाओं ने योजना शुरू होने की आस में अपने सारे दस्तावेज भी पूर्ण कर रखे हैं। उन्हें इंतजार है तो प्रदेश सरकार के आदेश का, जिसके बाद वह फार्म भरकर लाइली बहना योजना में शामिल हो जायेंगी। गौरतलब रहे कि पूर्व में लाइली बहना योजना में आयु की बाधयता थी। पूर्व में 23 से 59 वर्ष की तक की आयु की विवाहिताओं को ही योजना का लाभ मिल रहा था। इसमें भी कई महिलाएं ऐसी हैं, जिन्होंने योजना का फार्म तो भरा था, लेकिन वह योजना में शामिल नहीं हो पाईं वहीं कई दस्तावेजों की कमी सहित अन्य कारणों से योजना में शामिल नहीं हो पाईं। ऐसी महिलाएं अब लाइली बहना योजना का पंजीयन पुनः शुरू होने का इंतजार कर रही हैं, ताकि उन्हें भी लाइली बहना योजना का लाभ मिल सके।

लूट की तीन वारदातों का खुलासा, चार नाबालिग गिरफ्तार

बाइक पर घूमकर राहगीरों से लूटपाट करते थे आरोपी

बैतूल। कोतवाली पुलिस ने लूट की तीन अलग-अलग वारदातों का खुलासा करते हुए 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोटरसाइकिल से घूम-घूमकर राह चलते व्यक्तियों से मोबाइल फोन, नकदी एवं वाहन छीनने की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से लूट में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल (एचएफ डीलक्स), 05 मोबाइल फोन एवं नकद राशि बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 के विरुद्ध पूर्व में हत्या का अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 20 जनवरी 2026 को अथर्व दुबे की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं मोबाइल लक्की ढाबा के पास शाम लगभग 5.16 बजे छीना गया। 30 जनवरी को फुलेसिंह की मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं 150 रुपये हॉइवे फोरलेन से शाम लगभग 7 बजे लूटे गए। इसी तरह तीसरी घटना 9 फरवरी 2026 को हुई। सुरुज का बैग, जिसमें 5000 रुपये थे, टिगारिया से लापाइरि मार्ग पर छीना लिये थे। आरोपियों द्वारा बैतूलगंज के भी एक किसान व्यवसायी को लूटने की योजना बनाई थी। पुलिस



ने इन अलग-अलग वारदातों का खुलासा करते हुए 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने गंज के एक व्यापारी को भी लूटने की योजना बनाई थी। उक्त कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी श्री सुनील लाटा के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। संपूर्ण कार्यवाही में थाना कोतवाली

प्रभारी निरीक्षक देवकर डेहरिया के नेतृत्व में उप निरीक्षक उत्तम मस्तकार, उप निरीक्षक वसंत अहले, प्रधान आरक्षक शिव उडके, प्रधान आरक्षक तरुण पटेल, आरक्षक अनिरुद्ध यादव, आरक्षक नितिन चौहान, आरक्षक विशाल, आरक्षक दीपेन्द्र सिंह एवं आरक्षक राजेंद्र धाडसे की सहायता में थाना कोतवाली

चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर आवश्यक सुधार और मरम्मत के दीर्घ कालिक कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं: संभागायुक्त

बैतूल। संभागायुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी की अध्यक्षता में बैतूल में संभागीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक मिथलेश कुमार शुक्ला, मुख्य वन संरक्षक मधु वी. राज, वन संरक्षक अशोक कुमार, कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मोना, कलेक्टर हर्दा सिद्धार्थ जैन, पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन, पुलिस अधीक्षक हर्दा, पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम, डीएफओ नवीन गर्ग, डीएफओ लक्ष्मीकांत वासनिक सहित बैतूल, हर्दा एवं नर्मदापुरम जिलों के जिला पंचायत सीईओ तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संभागायुक्त श्री तिवारी ने संभाग के तीनों जिलों में राहवीर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित सहायता मिल सके तथा जीवन बचाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्राप्त हो। कैशलेस स्कीम और राहत योजना पर विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया ज्ञान उन्होंने कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों की पहचान कर जोनल प्लान तैयार करें, जहां आपातकालीन वाहनों के आवागमन में बाधा आती है। बैठक में तीनों जिलों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स तथा सुधारात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक सुधार एवं आवश्यकतानुसार रिमूवल कार्य किया जाए। संबंधित सड़क निर्माण विभाग आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि प्रमुख सड़कों से जुड़ने वाली गौण सड़कों के जंक्शनों पर सुरक्षा मानकों को अनुरूप सुधार एवं मरम्मत कार्य किए जाएं। परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा सड़क विकास निगम द्वारा सेम्टी ऑर्डर के प्रमुख बिंदुओं पर नियमित समीक्षा कर सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाएं। संभागायुक्त श्री तिवारी ने गत वर्ष तीनों जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

पेयजल अंतराल का विवाद नगर पालिका अध्यक्ष के दखल के बाद थमा पार्षदों के विरोध पर एक दिन के अंतराल से जारी रहेगी पेयजलापूर्ति

आमला। नगर पालिका में जल शाखा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों और नगर पालिका परिषद की सहमति के बिना वर्तमान में पूरे शहर में एक दिन के अंतराल से की जा रही पेयजलापूर्ति को बदलकर 2 दिन के अंतराल से करने पर और पार्षदों के विरोध के बाद बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष ने पूरे मामले में दखल देकर फिलहाल विवाद का पटाक्षेप कर दिया है।



इस मामले में मीडिया में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद नगर पालिका आमला के अध्यक्ष नितिन गाडरे ने नगर पालिका पहुंचकर पार्षदों के साथ चर्चा की और जलशाखा के एक तरफ निर्णय पर फिलहाल रोक लगा दी है। जल शाखा के एक तरफ निर्णय का विरोध दर्ज कराने नपा पहुंचे पार्षद अलका मानकर, पद्मिनी भूमकर, नीलम साहू, खुशबू अतुलकर, सुधीर अंबाडकर और राकेश शर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष को कर्मचारियों की निरक्षरता और बिना परिषद की सहमति के निर्णय लेने पर घोर आपत्ति दर्ज की थी। नगर पालिका में पार्षदों के विरोध के बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने जल शाखा के विभाग के एकतरफा निर्णय लेने पर फटकार भी लगाई है। इस मामले में फिलहाल शहर में अध्यक्ष के दखल के बाद एक दिन के अंतराल से पेयजलापूर्ति होती रहेगी, इस दौरान शहर के लोगों ने पार्षदों का आभार भी जताया है।

नगर पालिका अध्यक्ष ने 27 फरवरी को बुलाई परिषद की आपात बैठक

इधर पर जलापूर्ति पर 1 दिन के अंतराल को बढ़ाकर 2 दिन करने पर छिड़े घमासान के बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने परिषद की 27 फरवरी को आपात बैठक बुलाई है, यहां उपस्थित पार्षदों के आग्रह पर आगामी जल संकट से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में शहर के कई स्थलों पर नलकूपों में मोटर लगाने पर भी विचार किया जाएगा, इसके अलावा संभवतः

बैठक के बाद सभी पार्षद शहर के सबसे पुराने और परंपरागत जल स्रोत चिकना नाला का भी निरीक्षण करेंगे। माना जा रहा है, कि यहां चिकना नाला को लेकर परिषद कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है।

एक दर्जन से ज्यादा नलकूपों का अधिग्रहण करेगी नगर पालिका

आगामी जल संकट से निपटने के लिए नगर पालिका अपने सभी परंपरागत जल स्रोतों के अलावा कोई दर्जन भर निजी नलकूपों का भी अधिग्रहण करने जा रही है, इसके लिए नगर पालिका में वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति से नलकूपों के अधिग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर नगर पालिका चिकना नाला एवं नए नलकूपों का अधिग्रहण करती है तो, शहर में गर्मी के मौसम में भी पेयजल व्यवस्था को बेहतर चलाया जा सकता है। मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे ने बताया है कि शहर की जनता की प्राथमिकता और समस्याएं सबसे पहले हैं, हम शहर को बेहतर की ओर ले जाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों को नॉन-अटेंडेड रखने पर अधिकारियों पर

अधिरोधित की जाए पेनल्टी : कलेक्टर सोनिया मीना

नर्मदापुरम (निप्र)। आयोजित समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं अभियानों तथा अन्य विभागीय कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक के दौरान समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि नरवाई प्रबंधन के संबंध में ठोस एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यकतानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाएं तथा संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

बैठक में कलेक्टर ने कृषि विभाग, एसडीएम एवं समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर नरवाई प्रबंधन के लिए उपयुक्त योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि गेहूँ की कटाई के बाद अवशेषों का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए भूसा तैयार किया जाए तथा उसके सदुपयोग की भी व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने कृषि अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि नरवाई प्रबंधन में उपयोग होने वाले यंत्रों की सूची उनके धारकों के नाम एवं संपर्क सूत्र सहित तैयार कर पंचायत भवनों, तहसील कार्यालयों एवं अन्य आवश्यक सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाए, जिससे किसानों को यंत्रों की उपलब्धता की जानकारी सहज रूप से प्राप्त हो सके। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने राजस्व,



नगरीय निकाय, सामाजिक न्याय सहित अन्य संबंधित विभागों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निराकरण पर प्रारंभ से ही गंभीरता के साथ ध्यान केंद्रित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि प्राप्त शिकायतों के अनुपात में उनका समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन के सभी प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए। बैठक में कलेक्टर ने नॉन-अटेंडेड शिकायतों पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों द्वारा शिकायतों को नॉन-अटेंडेड रखा गया है, उन्हें नोटिस जारी कर आवश्यकतानुसार पेनल्टी अधिरोधित करने की कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक के दौरान न्यायालय

में लंबित अवमानना प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए जवाब-दावे समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर जवाब प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने न्यायालय के अवमानना प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जवाब की अनुपालन रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति विधि शाखा में अनिवार्य रूप से दर्ज कराई जाए।

कलेक्टर ने फायर एनओसी से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि लंबित मामलों में विस्तृत प्रकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने समस्त एसडीएम को

निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र में संचालित होटल, रिजॉर्ट एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की जांच कर फायर एनओसी तथा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक प्रमाण पत्रों की विधिवत जांच सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में कलेक्टर ने 'संकल्प से समाधान' अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त किए जाएं, ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को अभियान की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि अभियान अवधि में आयोजित होने वाले शिविरों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभागों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उन्नीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत समितियों का गठन किया जाए। गठित समिति द्वारा नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाए साथ ही कार्यालय के कर्मचारियों को भी कार्यालय में प्रवेश किया जाए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त समिति में कार्यशाला आयोजित कर सभी विभागों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए। बैठक के दौरान एडीएम श्री राजीव रंजन पांडे अपर कलेक्टर श्री अनिल जैन डिप्टी कलेक्टर डॉ बबिता राठौर, श्रीमती सरोज परिहार, श्रीमती नीता कोरी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

खंड स्तरीय सीनियर बालक छात्रावास में विद्यार्थियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण



विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा जिले में संचालित सभी छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए हर क्षेत्र में विशेष पहल कु जा रही है उनके निर्देशानुसार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं नियमित निगरानी के दायित्वों का विशेष तौर पर मानीटरिंग की जा रही है। छात्रावासी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण उद्देश्य से खंड स्तरीय सीनियर बालक छात्रावास नटेरन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रावास में निवासरत सभी विद्यार्थियों का चिकित्सकीय दल द्वारा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उनकी ऊँचाई, वजन, हीमोग्लोबिन, आँख, त्वचा एवं अन्य सामान्य बीमारियों की जांच की गई। परीक्षण के दौरान कुछ विद्यार्थियों में सामान्य स्वास्थ्य समस्याएँ पाई गईं, जिन्हें आवश्यक परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया गया। साथ ही गंभीर समस्या वाले विद्यार्थियों को आगे की जांच हेतु संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने की सलाह दी गई। इस अवसर पर चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को स्वच्छता, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के संबंध में जानकारी दी।

ग्रीष्म ऋतु के लिए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रभावी पेयजल कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रगति लाने के लिए श्रम पदाधिकारी एवं सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा।

राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने राजस्व, खनिज, परिवहन और पंजीयन विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल-जल योजनाओं की समीक्षा में



उन्होंने निर्देशित किया कि सभी एकल ग्राम नल-जल योजनाओं को शीघ्र 'हर घर जल' घोषित करने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। उन्होंने जनपद सीईओ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए ग्रामवार पेयजल प्रबंधन की प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए ताकि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो

सके। बैठक में फायर स्टेशन हेतु भूमि आवंटन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की तिथियों का निर्धारण, किसानों के फॉर्मर आईडी का शत-प्रतिशत निर्माण, आधार नामांकन, फसल सांख्यिकीय संकलन सहित अन्य समसामयिक विषयों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर पूरा करें तथा प्राप्त वित्तीय आवंटन का सदुपयोग सुनिश्चित करें। लापरवाही से आवंटन लेनस होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

साक्षित समाचार

आयुष्मान भारत योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी, सभी बीएमओ को अधिक से अधिक कार्ड बनवाने के निर्देश

विदिशा (निप्र)। जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है। इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ अमले के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष निशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति नहीं होना चिंता का विषय है। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने बीएमओ को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैदानी स्तर पर कार्यरत एएनएम, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को सक्रिय करते हुए घर-घर संपर्क कर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। साथ ही जिन क्षेत्रों में प्रगति कम है, वहां विशेष शिविर आयोजित कर कार्य में तेजी लाई जाए। अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए कि आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने आशवासन दिया कि शासन के निर्देशानुसार अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा, जिससे जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

मातोश्री वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित

बैतूल (निप्र)। उड़दन स्थित मातोश्री वृद्धाश्रम में सोमवार 23 फरवरी को स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन कर योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। शिविर का उद्देश्य आमजन एवं वृद्धजनों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में आयुष विभाग ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए कैसे आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है विषय पर विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया। शिविर में संतुलित भोजन, स्वच्छ पेयजल, योग और आयुर्वेद के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। योग हेतु जिला नोडल अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह शाक्य ने उपस्थितजनों को बताया कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी सुदृढ़ होता है। इसके बाद योग सहायक भूपेन्द्र द्वारा विभिन्न योगासन और प्राणायाम का व्यावहारिक अभ्यास सत्र आयोजित किया गया, जिसमें वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर ने आयुर्वेद पद्धति की विस्तृत जानकारी देते हुए दैनिक जीवन में आयुर्वेदिक दिनचर्या, आहार-विहार और घरेलू उपचारों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद अपनाकर अनेक रोगों से बचाव संभव है और दीर्घकालीन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की गई। शिविर के अंत में उपस्थितजनों को नियमित योग करने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और आयुर्वेदिक सिद्धांतों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम ने विशेष रूप से वृद्धजनों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रेलवे-सड़क सहित अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों की नियमित समीक्षा होगी

सीहोर (निप्र)। मध्यप्रदेश में चल रहे रेलवे, सड़क सहित अन्य अधोसंरचना के बड़े प्रोजेक्ट की प्रतिमाह प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन और भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में सचिव समन्वयक श्री मनोज कुमार गोविल ने सोमवार को मंत्रालय में संयुक्त रूप से पी.एम मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में केंद्र के महत्वपूर्ण 11 प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-सीमा अनुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन करें और पी.एम गति शक्ति पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट से नियमित अवगत कराएं। मुख्य सचिव श्री जैन ने जललपुर में प्रस्तावित 100 बिस्तरीय ई.एस.आई अस्पताल के लिए शीघ्र ही भूमि आवंटन के लिए आवेदन देने के श्रम विभाग को निर्देश दिए और कहा कि आवेदन प्राप्त होने के दो-तीन माह में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। इस दौरान इंद्रौर-धुबनी नई रेललाइन, रामगंज मंडी से भोपाल नई रेललाइन परियोजना, सतना-रीवा रेलवेलाइन के दोहरा करण कार्य, इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाइन, रतलाम-महु-खंडवा अकोला गेज परिवर्तन कार्यों की गहन समीक्षा की गयी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे भूमि अधिग्रहण के सभी प्रकरणों के निराकरण और उनमें पारित मुआवजा राशि के वितरण कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच अनुभूतियों आदि के लिए लगने वाले समय को न्यूनतम करने के भी निर्देश दिए।

कहा कि प्रशिक्षण में दी गई सभी जानकारियों को भली-भांति समझकर कार्य करें। उन्होंने जनगणना कार्य को पूरी निष्ठा, सटीकता एवं समयबद्ध तरीके से संपादित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने बैठक में नेशनल हाइवे एवं रेल परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में विलंब न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारी समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तित करने की प्रक्रिया को गति देने तथा वनाधिकार दावों की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने गिरदावरी कार्य में सरसों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों को भी शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि वास्तविक उत्पादन का सही आकलन हो सके। उन्होंने गेहूँ उत्पादन के लिए प्रतिदिन अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन कराने तथा प्रगति की सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। साथ ही उन्होंने ई-टोकन व्यवस्था के माध्यम से खाद वितरण



सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को निर्धारित समय पर उर्वक उपलब्ध हो सके और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके। बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, श्री जमील खान, श्री रविंद्र परमार, एसडीएम जी नितिन टाले, श्री तन्मय गौड़, श्रीमती स्वाति मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रेम सिंह गौड़ सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

नरवाई जलाने पर सख्ती बरतने और किसानों को जागरूक करने के निर्देश : बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने जिले में

नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है तथा आमजन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। कलेक्टर ने राजस्व, कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से निगरानी रखने तथा ऐसे मामलों में तत्काल दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक करना भी आवश्यक है। कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा पंचायतों में बैठकों एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से नरवाई प्रबंधन के

वैकल्पिक उपायों की जानकारी दी जाए, ताकि किसान पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बन सकें।

संकल्प से समाधान अभियान के प्रभावी संचालन के निर्देश, अभी तक 64802 प्रकरणों का निराकरण : बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाये। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसलिए अभियान को पर्याप्त मजबूती बनाया जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि क्लस्टर लेवल पर आयोजित किए जाने वाले शिविर सुव्यवस्थित एवं प्रभावी हों। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें। उन्होंने यह भी कहा कि शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए, ताकि जनसहभागिता बढ़े और आमजन की समस्याओं का समाधान पारदर्शिता

के साथ हो सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अभियान के तहत अभी तक 69837 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 64802 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अधिक से अधिक पंजीयन के निर्देश : कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य श्रमिकों को वृद्धावस्था में समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, इसलिए पात्र हितग्राहियों तक योजना की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाई जाए। कलेक्टर ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विशेष कैम्प आयोजित कर पंजीयन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंजीयन कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करें। लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नहीं होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।



देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। जिले में 1,231 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही 1,004 किसानों द्वारा नरवाई जलाने के बजाय उसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया तथा 17,400 किसानों को रबी फसल के संबंध में जागरूक किया गया।

इसके अलावा 3,016 किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई तथा 1,570 किसानों के खेतों में जैविक खाद एवं जीवामृत के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। 3,512 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल विविधीकरण किया गया तथा 6,914 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।

कृषि रथ अभियान के दौरान विभिन्न शासकीय

योजनाओं के लिए भी आवेदन प्राप्त किए गए। इनमें आयुष्मान कार्ड के लिए 190, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 213, पीएम किसान योजना के लिए 423 तथा फार्म आईडी एवं ई-कैवाईसी के लिए 160 आवेदन प्राप्त हुए। कुल 986 किसानों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किया।

कृषि विभाग के उप संचालक श्री केएस खर्चेडिया ने बताया कि कृषि रथ अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों से जोड़ना, उत्पादन बढ़ाना एवं उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना है। इस अभियान से किसानों में जागरूकता बढ़ी है और उन्हें खेती में नई तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा मिली है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन से बदली बलराम सिंह गुर्जर की किस्मत

पशुपालन व्यवसाय से प्रतिमाह 25 से 30 हजार रुपये की आय, क्षेत्र के लिए बने प्रेरणास्रोत

नर्मदापुरम (निप्र)।

सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले के ग्रामीण अंचलों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक शक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हो



रही है। इस बात की यथार्थ करती कहानी है विकासखंड बनखेड़ी के ग्राम रिडेड़ा निवासी श्री बलराम सिंह गुर्जर पिता श्री हज्जी गुर्जर जिन्हें राष्ट्रीय पशुधन मिशन एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (पशुपालन) के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया। योजना से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और आज वे आत्मनिर्भर पशुपालक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं।

कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले श्री गुर्जर प्रारंभ में अन्य

पशु बेचने पड़े, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परिवार की मद्दतियों एवं अन्य सदस्यों ने भी पशुपालन कार्य में सक्रिय सहयोग दिया। वर्तमान में उनके पास 05 भैंस एवं 06 गाय हैं,

जिनसे प्रतिदिन लगभग 70 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। इससे उन्हें प्रतिमाह लगभग 25 हजार से 30 हजार रुपये की आय प्राप्त हो रही है।

कृषि योग्य भूमि एवं घर में पर्याप्त स्थान न होने के कारण वे समय-समय पर पशुओं का विक्रय कर अतिरिक्त आय भी अर्जित करते हैं। आज उनका पूरा परिवार इसी व्यवसाय पर निर्भर है। योजना से जुड़ने के पूर्व उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी तथा आय का एकमात्र साधन अन्य किसानों से दूध खरीदकर बेचना था।

वरिष्ठ कथाकार मृदुला गर्ग, अलका सरावगी सहित सात रचनाकार सम्मानित



भोपाल। सुप्रतिष्ठित कथाकार, शिक्षाविद तथा विचारक जगन्नाथ प्रसाद चौबे 'वनमाली जी' के रचनात्मक योगदान और स्मृति को समर्पित संस्थान 'वनमाली सृजन पीठ' के प्रतिष्ठा आयोगन राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान समारोह-2026 का भव्य शुभारंभ स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, भोपाल के मुक्ताकाश मंच पर सुप्रसिद्ध लोकगायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया के कबीर गायन से हुआ।

यह सम्मान समारोह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ उड़िया कथाकार प्रतिभा राय के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

सम्मान समारोह में 'वनमाली कथाशीर्ष सम्मान' से वरिष्ठ रचनाकार मृदुला गर्ग को एवं 'राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान' से वरिष्ठ कथाकार अलका सरावगी को सम्मानित किया गया। दोनों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं एक-एक लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया 'वनमाली कथा आलोचना सम्मान' महेश दर्पण को, 'वनमाली कथा मध्यप्रदेश सम्मान' वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष (भोपाल) को, 'वनमाली युवा कथा सम्मान' युवा कथाकार कुणाल सिंह को, 'वनमाली कथेतर सम्मान' अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र को प्रदान किये गए। साहित्य के क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहला वनमाली डिजिटल साहित्य अवदान सम्मान अंजुम शर्मा को प्रदान किया गया। इन सभी सम्मानित रचनाकारों को शॉल-श्रीफल प्रशस्ति पत्र एवं इक्यावन-इक्यावन हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया।

वनमाली सृजन पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ कवि कथाकार श्री संतोष चौबे ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 'विश्व रंग' के अंतर्गत वनमाली सृजन पीठ द्वारा प्रदान किए गये 'वनमाली कथा सम्मान' समकालीन कथा परिदृश्य में लोकतांत्रिक एवं मानवीय मूल्यों की तलाश में जुटे कथा साहित्य की पुनः प्रतिष्ठा करने एवं उसे

समुचित सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित द्विवार्षिक पुरस्कार है।

इस अवसर पर वरिष्ठ लेखिका एवं इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए की कार्यकारी संपादक डॉ. विनीता चौबे, वरिष्ठ कथाकार एवं वनमाली सृजन पीठ, भोपाल के अध्यक्ष मुकेश वर्मा, एस.जी.एस.यू. के कुलगुरु डॉ. विजय सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पत्रिका 'वनमाली कथा' के न फरवरी अंक और वनमाली सृजन पीठ के मुखपत्र वनमाली वार्ता का लोकार्पण किया गया।

साथ ही वनमाली जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर केंद्रित और वनमाली सम्मान समारोह पर केंद्रित लघु फिल्म तथा विश्व रंग के सात वैश्विक आयोजनों पर केंद्रित फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

समारोह का संचालन टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र के निदेशक विनय उपाध्याय ने किया। सम्मानित रचनाकारों की प्रशस्ति का वाचन डॉ. संगीता पाठक ने किया गया। आभार डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी, कुलाधिपति, स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, भोपाल ने व्यक्त किया। अतिथियों का स्वागत डॉ. नितिन वत्स, डॉ. संगीता जौहरी, डॉ. सितेश सिन्हा, संजय सिंह राठौर ने किया। समारोह का संयोजन वनमाली सृजन पीठ की राष्ट्रीय संयोजक ज्योति रघुवंशी ने किया।

इस अवसर पर बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय किया कुलगुरु डॉ. जैन, आर.एन.टी.यू. के कुलगुरु डॉ. आश.पी. दुबे, वरिष्ठ रचनाकार शशांक, लीलाधर मंडलोई, बलराम गुमास्ता, राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, रामकुमार तिवारी, सविता भार्गव, डॉ. रेखा कस्तवार, डॉ. जवाहर कर्नावट, संजय शेफर्ड, अरुणेश शुक्ल, मोहन सगोरिया, कैलाश मांडलेकर, नीलेश रघुवंशी, निरंजन श्रोत्रिय, घनश्याम मैथिल, सुरेश पटवा, देवीलाल पाटीदार, करुणा राजगुरुकर, वामनराव, सुदर्शन सोनी आदि सहित सैकड़ों की संख्या में युवा साहित्यप्रेमियों, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक उपस्थिति दर्ज कराई।

राजधानी

उज्जैन में शंकराचार्य मठ की तीन मंजिला बिल्डिंग पर चला बुलडोजर

सिंहस्थ 2028 से पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, धर्मशालाएं भी तोड़ी जा रही

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत नगर निगम ने बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। निगम अमले ने पुलिस बल के साथ नृसिंह घाट से लालपूल ब्रिज मार्ग तक 2016 के बाद बने पक्के निर्माणों को हटाया। यह कार्रवाई जोन क्रमांक 03 क्षेत्र में की गई।

प्रशासन ने बताया कि सिंहस्थ मेले के लिए साधु-संतों के डेरों, टेंट और श्रद्धालुओं की पार्किंग के लिए जगह खाली कराई जा रही है।

आश्रम और धर्मशाला के निर्माण भी हटाए गए

कार्रवाई के दौरान नर्मदा घाट क्षेत्र स्थित शंकराचार्य मठ में पुण्यानंद गिरी महाराज के आश्रम में भी कार्रवाई की गई। यहां 54 कमरों वाला तीन मंजिला भवन बनाया गया था, जिसमें एसी और नॉन-एसी कमरे थे। इस भवन में अवैध रूप से होटल संचालित किया जा रहा था। प्रशासन के अनुसार तीन मंजिला होटल करीब 10 हजार से 15 हजार वर्गफुट क्षेत्र में बनाया गया था। नगर निगम की टीम ने इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की।

इधर, नरसिंह घाट रोड पर करीब 60x80 फीट के माधवानंद आश्रम और लगभग 80-



150 फीट क्षेत्र में बनी कलोता समाज की धर्मशाला को हटाया गया। इसके अलावा बागली समाज और अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है।

सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं- नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद बने सभी स्थायी निर्माण चिन्हित किए गए हैं। इस

क्षेत्र में स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है और सभी अवैध ढांचे हटाए जाएंगे।

अपर आयुक्त संतोष टैगोर ने बताया कि जिला प्रशासन से मिली सूची में अवैध निर्माणों की जानकारी थी। सिंहस्थ मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन निर्माणों को हटाया जा रहा है। सिंहस्थ क्षेत्र करीब 180 हेक्टेयर में फैला हुआ है।

बीहर रिवर फ्रंट शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करें : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में रीवा शहर में पुनर्गठन कार्ययोजना की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं, अधोसंरचना उन्नयन तथा सौंदर्यीकरण कार्यों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विशेष रूप से बीहर नदी के रिवर फ्रंट विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि नदी के पूर्वी तट का सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि पश्चिमी तट का कार्य शेष है। उन्होंने पश्चिमी तट पर शेष रिवर फ्रंट कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के



निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि बीहर नदी के दोनों तटों का समग्र विकास

होने से रीवा शहर को विशिष्ट पहचान मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थल

उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही पुनर्गठन कार्ययोजना अंतर्गत अन्य प्रस्तावित कार्यों को भी समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाने, आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियों को शीघ्र पूर्ण करने तथा समय-व्यय के साथ कार्य करने पर बल दिया गया। उन्होंने केंद्रीय जेल रीवा में पुनर्गठन कार्ययोजना के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के आयुक्त श्री गौतम सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बड़ा तालाब-कैचमेंट एरिया में 10 साल में सैकड़ों नए निर्माण

भोपाल सांसद-कलेक्टर की फटकार के बाद फिर कार्रवाई, टास्क फोर्स रखेगी नजर

भोपाल (नप्र)। भोपाल की लाइफ लाइन बड़ा तालाब अतिक्रमण की जकड़ में है। पिछले 10 साल में बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में ही सैकड़ों पक्के निर्माण बन गए। कुछ तो मुनारों से ही सटकर बने हैं। दूसरी ओर, भद्रभदा की 350 से ज्यादा झुगियां ही हटाई जा सकी हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम को एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्राइबल) कई बार फटकार भी लगा चुका है।

हाल ही में सांसद आलोक शर्मा ने अफसरों की बैठक भी ली थी और बड़ा तालाब के अतिक्रमण को लेकर जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद जिला प्रशासन एक्टिव हुआ है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स भी बनाई है, जो कार्रवाई पर नजर रखेगी। ऐसे में प्रशासन जल्द ही बड़े स्तर पर कार्रवाई कर सकता है। बुधवार को जिम्मेदार एसडीएम-तहसीलदारों के बीच कार्रवाई को लेकर चर्चा भी हुई। अब तक 3 बार सर्वे,



ठोस कार्रवाई नहीं बता दें कि बड़ा तालाब का बीते दस साल में 3 बार सर्वे हो चुका है। इनमें बड़ी संख्या में अतिक्रमण सामने आए, लेकिन सर्वे रिपोर्ट का आज तक पता नहीं है। इस वजह से बैरागढ़, खान्गवाड़, सूरज नगर, गौरगांव, बिसनखेड़ी समेत कई

जगहों पर अतिक्रमण हुए। कई मैरिज गार्डन, फार्म हाउस, स्कूल-कॉलेज, घरों की सीमाएं बड़ा तालाब में हैं। सांसद आलोक शर्मा ने दो दिन पहले ही अफसरों की बैठक लेकर बड़ा तालाब के अतिक्रमण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी।

एक्सपर्ट राशिद नूर की मानें तो शहरी सीमा में 50 मीटर और ग्रामीण सीमा में 250 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन एफटीएल मुनार से सटकर ही पक्के निर्माण बन गए हैं। ऐसे 1 या 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों निर्माण हैं। भद्रभदा, बिसनखेड़ी, गौरगांव, बील गांव और सूरजनगर में बड़ी बिल्डिंग, फार्म हाउस, रिसॉर्ट भी देखने को मिल सकते हैं। हैरत की बात ये है कि बड़ा तालाब रामसर साइट भी है। बावजूद सालों से सिर्फ फाइलों में ही कब्जे हटें हैं। सूरजनगर में तो जिस जगह पर रामसर साइट है और नगर निगम की मुनार लगी है। ठीक उससे जुड़ी बिल्डिंग की बाउंड्रीवॉल है। यही पर नगर निगम की सीवेज लाइन भी बिछाई गई है। मुनार के पास सड़क भी भरी गई है, जो नियम के विरुद्ध है। दूसरी ओर गौरगांव से बील गांव की तरफ सड़क भी तालाब के बीच से ही गुजरी है।

मुनारों में भी फर्जीवाड़ा...दो तरह की मुनारे मिले

बड़ा तालाब के किनारों पर भू-माफिया सक्रिय हैं, जो कम दाम पर प्लाट देने का वादा कर रहे हैं। उन्होंने और लोगों ने इस दायरे को लेकर ही भ्रम की स्थिति भी खड़ी की है।

जिन मुनारों से एफटीएल की सीमा तय होती है, उन्हीं में फर्जीवाड़ा किया गया है। मौके पर एफटीएल बताते वाली 5 तरह की मुनारे लगे हुए मिले हैं। इनमें से एक में बीएमसी यानी, भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लिखा है। बाकी पर सफेद रंग है। लिखा कुछ नहीं है। इन्हीं फर्जी मुनारों के आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण हैं।

बदमाशों ने युवकों को बेहोश होने तक पीटा..

भोपाल में पत्थर से मुंह-नाक को कुचला, 38 सेकंड में 12-15 वार, केस वापस नहीं ले रहे थे

भोपाल (नप्र)। भोपाल के भीम नगर में 6 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने मंगलवार रात दो युवकों को बेहोश होने तक पीटा। चाकू-छुरी, पत्थर से मुंह-नाक को कुचल दिया। लात-घूसों से भी मारा। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक घायलों में रावेंद्र सेन और सौरभ विश्वकर्मा शामिल हैं। 38 सेकंड के भीतर करीब 12-15 वार किए गए। हमला पुरानी रंजिश के चलते किए गया है। मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अवकू गैंग ने की वारदात

पुलिस के मुताबिक, अकू उर्फ आकाश और विशाल चपटी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रावेंद्र सेन पर हमला किया। यह हमला एक पुराने केस में समझौता करने से मना करने पर गुस्से में किया गया। रावेंद्र और उसके साथी को आरोपियों ने जघमकर पीटा है।

दोस्त की ओर से एफआईआर दर्ज की गई- रावेंद्र के दोस्त सौरभ विश्वकर्मा ने पुलिस



को बताया कि वे हनुमान मंदिर के पास खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी अकू, विशाल और उनके साथियों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में रावेंद्र के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि बीच-बचाव करने की कोशिश में उसे भी गंभीर चोटें आईं।

किसान ने फांसी लगाकर सुसाइड किया

पिता बोले पत्नी धमकाती थी, केस भी दर्ज करा रखा था



भोपाल (नप्र)। भोपाल के इंटखेड़ी में रहने वाले एक किसान ने मंगलवार रात घर में सल्फास की गोली खा ली। इलाज के दौरान बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पत्नी से विवाद के चलते आत्महत्या की बात पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आई है।

गोलू साहू (28) हनुकुंद साहू रायपुर गांव इंटखेड़ी का रहने वाला था। वह किसानी करता और मारवाड़ी रोड पर एक कॉस्मेटिक्स शॉप पर काम भी करता था। उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा रखा था। बीते एक साल से पत्नी अपने मायके में रह रही है। लगातार कॉल पर दूसरे केस में फंसाने की धमकी देती थी।

बच्चों से नहीं मिलने देती थी पत्नी

गोलू साहू के दो बच्चे हैं। पत्नी गोलू को बच्चों से भी नहीं मिलने देती थी। इस बात को लेकर वह तनाव में रहते थे। मृतक के पिता का आरोप है कि बहू की आए दिन की धमकियों से तंग आकर बेटे ने मंगलवार रात को सल्फास खा लिया। इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उनकी मौत हो गई।

जायका टीम ने किया भोपाल में एमपी ट्रांसको की ट्रांसमिशन लाइन एवं महावड़िया सब स्टेशन का सूक्ष्म मूल्यांकन

सब स्टेशन बनने से हुए लाभ के संबंध में स्थानीय व्यापारियों से किया वार्तालाप

भोपाल (नप्र)। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जायका) द्वारा मध्यप्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिये मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) में संचालित जायका-2 वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत भोपाल में हुए कार्यों का विस्तृत निरीक्षण कर उनका सूक्ष्म मूल्यांकन किया गया। जायका जापान की इवैल्यूएटर सुश्री हिंसाए ताकाहाशी एवं जायका के भारतीय प्रतिनिधि श्री कुनाल गुप्ता ने निर्माण कार्यों, उनकी गुणवत्ता, उपयोगिता तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्रियान्वयन की बारीकी से जांच-पड़ताल की। महावड़िया सब स्टेशन एवं लाइन का किया निरीक्षण- निरीक्षण के दौरान टीम ने सर्वप्रथम 132 केवी सब स्टेशन महावड़िया तथा इसके लिए निर्मित 132 केवी महावड़िया-मुगलियाश्रप डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का निरीक्षण कर सूक्ष्म मूल्यांकन किया। इवैल्यूएटर सुश्री ताकाहाशी ने लोन स्वीकृति के समय प्रस्तुत प्रारंभिक योजना, परियोजना के क्रियान्वयन, स्थापित उपकरणों की गुणवत्ता, लागत एवं रखरखाव से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

सब स्टेशन के संचालन-संधारण की जानकारी प्राप्त

जायका टीम ने सब स्टेशन के संचालन एवं संधारण कार्यों की जानकारी, पदस्थ कर्मचारियों की योग्यता और उनके दैनिक कार्यों का विवरण, आपातकालीन स्थिति से निपटने की कार्ययोजना तथा सब स्टेशन से पर्यावरण को होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के संबंध में भी जानकारी ली। निरीक्षण उपरत जायका टीम ने सब स्टेशन एवं ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उपयोगिता जानने के लिए व्यापारियों से की चर्चा- जायका द्वारा वित्त पोषित फंड से निर्मित महावड़िया सब स्टेशन की उपयोगिता के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेने के साथ जायका टीम ने सब स्टेशन के नजदीक स्थित व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में जाकर उनका प्रत्यक्ष फीडबैक भी लिया। व्यापारियों ने बताया कि सब स्टेशन के निर्माण से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब उन्हें पर्याप्त एवं निरंतर बिजली मिल रही है, जिससे व्यापार के संचालन करने में अब उन्हें आसानी हो रही है। इससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है।

उपभोक्ताओं ने बताये फायदे

जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जायका) की टीम ने भोपाल स्थित महावड़िया सब स्टेशन के मूल्यांकन एवं निरीक्षण के दौरान सबस्टेशन के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में हुए बदलावों की जानकारी ली गई। सबस्टेशन के सामने स्थित डेयरी के संचालक श्री दिनेश यादव (यादव डेयरी) ने बताया कि सन् 2021 के पूर्व में बिजली सप्लाई मंडीदीप सबस्टेशन से आती थी, जिसमें लाइन की लंबाई अधिक होने से अनेक बार ट्रिपिंग एवं वोल्टेज में उतार-चढ़ाव (फ्लक्चुएशन) की समस्या रहती थी।